भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

नव प्रभा

नवरत्न बीईएल कार्पोरेट कार्यालय की

ई गृह पत्रिका

आत्मनिर्भर भारत

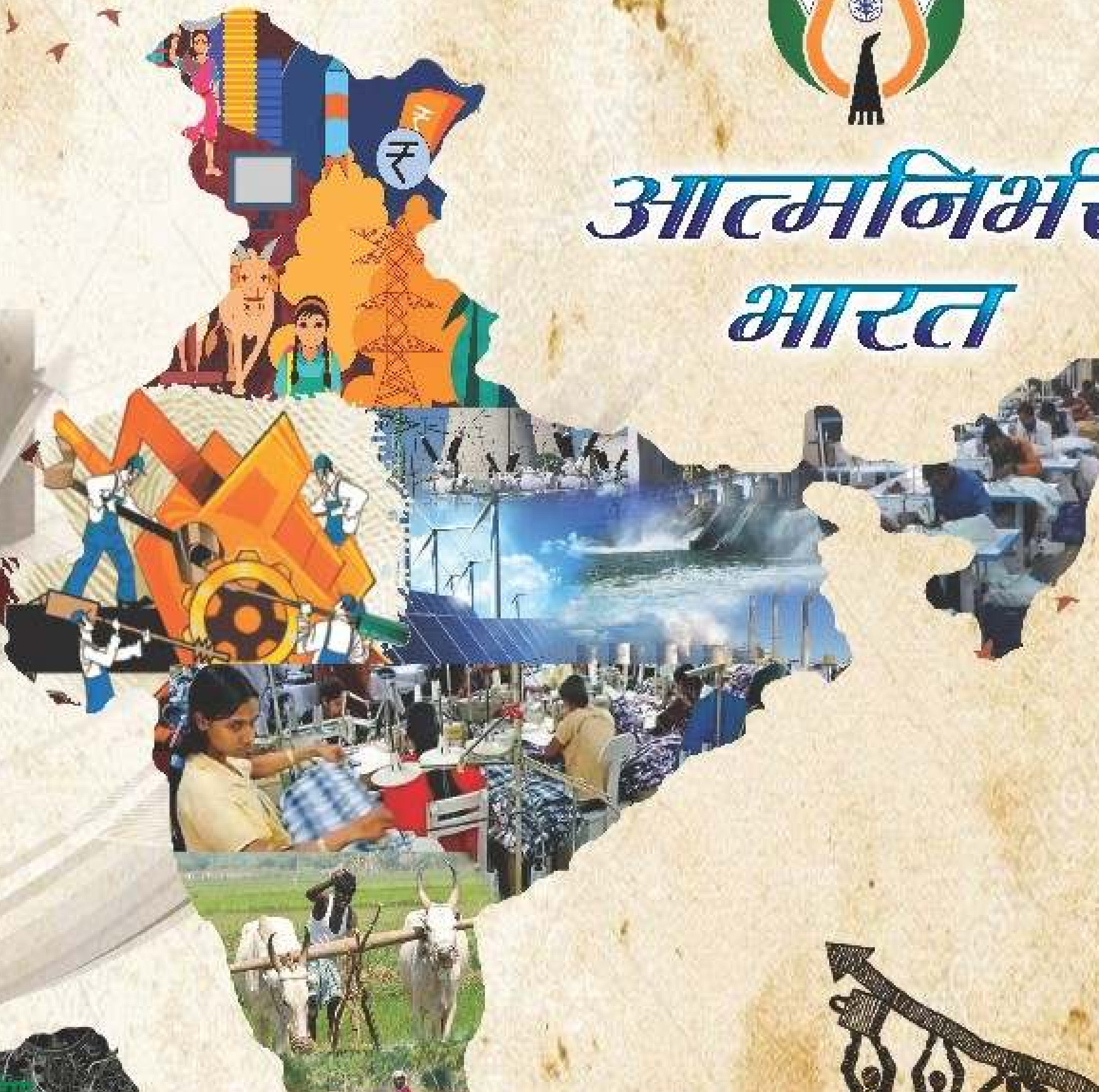

मेक इन इंडिया

अप्रैल – सितंबर 2020

अर्धवार्षिक ई गृह पत्रिका अंक- 09

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

दृष्टि

पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी में विश्व-स्तरीय उद्यम बनना।

ध्येय

रक्षा इलेक्ट्रॉनिकी और पेशेवर इलेक्ट्रॉनिकी के अन्य चुने हुए क्षेत्रों में गुणता, प्रौद्योगिकी और नवीनता के ज़रिए ग्राहक केन्द्रित, वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंपनी बनना।

मूल्य

- ग्राहक सर्वोपरि है ।
- पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना ।
- व्यक्तियों पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना ।
- टीम भावना को पोषित करना ।
- अत्यधिक कर्मचारी संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करना ।
- लोचता और नवीनता को प्रोत्साहित करना ।
- अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयत्न करना।
- संगठन का हिस्सा होने पर गर्व होना ।

नव प्रभा

अनुक्रमणिका

01	गृह मंत्री का संदेश	03
02	रक्षा मंत्री का संदेश	05
03	उच्चाधिकारियों के संदेश	07,09,11
04	हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा के पथ की ओर अग्रसर	15
05	कॉर्पोरेट कार्यालय की राजभाषा गतिविधियाँ	18–22
06	बीईएल की यूनिटों और कार्यालयों की राजभाषा गतिविधियाँ	23–33
07	भारत की आज़ादी से आत्मनिर्भर भारत बनने तक का सफर	34
08	स्वरोजगार का सृजन	38
09	"एमएसएमई"	39
10	ऐसा मेरा देश महान	41
11	आत्मनिर्भरता – राष्ट्रीय अभिप्राय	42
12	प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली	44
13	गुणवत्ता से मजबूत होगा लोकल	46
14	अब आ गया है समय	47
15	रक्षा क्षेत्र में स्वायत्त भारत	48
16	आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था	51
17	'ज्ञ' से ज्ञान	54
18	स्वदेशी अपनाएँ, भारत को आत्मनिर्भर बनाएँ	55
19	भारत सरकार की सार्थक पहल – स्टार्टअप इंडिया	57
20	भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति – सरकारी समर्थन, चुनौतियाँ और संभावनाएँ	60
21	रक्षामंत्री ने बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों को लॉन्च किया	65
22	आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बीईएल की एटीडीएस मारीच विनिर्माणी सुविधा	66
23	रणनीतिक उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए बीईएल का ई.ओ.आई. जारी	66

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020 - 21 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई–मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय / व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/ की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के डिजिटल उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहाँ संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	40%	20%	10%
		(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहाँ अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।		

अमित शाह,
गृह मंत्री
भारत
AMIT SHAH
HOME MINISTER
INDIA

सत्यमेव जयते

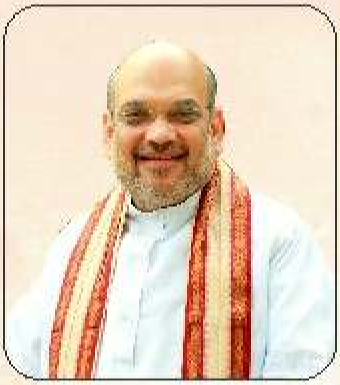

प्रिय देशवासियों!

हिंदी दिन के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ।

पूरी दुनिया में हमारा देश, एक अलग प्रकार का देश है। कई प्रकार की संस्कृतियाँ, कई प्रकार की कलाएं और कई प्रकार की भाषाओं का मेलजोल यहां पर दिखाई पड़ता है। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हम सभी दृष्टि से एक संपन्न राष्ट्र हैं। अनेक भाषाएं एवं संस्कृतियाँ हमारी न केवल विरासत हैं, हमारी ताकत भी हैं, इसलिए हमें इसको आगे बढ़ाना है। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे, इस गौरवशाली देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सदियों से, कई भाषाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है। हिंदी इसमें प्रमुख भाषा रही है और ये योगदान जो हिंदी का है इसको देश के कई नेताओं ने समय–समय पर सराहा है और हिंदी ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा और बाकी सारी भारतीय भाषाओं ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी के साथ बृज, बुंदेलखंडी, अवधि, भोजपुरी, अन्य भाषाएं और बोलियां इसका उदाहरण है। हिंदी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता, सुबोधता और स्वीकार्यता भी है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वग्राह्यता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया।

भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों की अविरल धारा, मुख्य रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है। हिंदी भाषा ने, बाकी स्थानीय भाषाओं को भी, बल देने का प्रयास किया है । हर राज्य की भाषा को, हिंदी ताकत देती है। हिंदी की प्रतिस्पर्धा कभी भी स्थानीय भाषा से नहीं रही, यह पूरे भारत के जनमानस में ज्यादा स्पष्ट होने की जरूरत है। 26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं का प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, जहाँ आवश्यक है या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए, हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है कि सरकारी कामकाज अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में किया जाए और अन्य स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों तथा बैंकों इत्यादि के कार्यालय प्रमुखों एवं वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि स्थानीय भाषाओं के साथ–साथ वे सरकारी कामकाज में, मूल रूप से हिंदी का प्रयोग करें ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को भी अपना कार्य हिंदी में करने की प्रेरणा मिले।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक संसाधन–संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और इसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से, हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा भी मिल रही है। इससे देश की युवा पीढ़ी भाषा के साथ जुड़ने की ओर अग्रसर हुई है। बस, आवश्यकता इस बात की है कि आगामी पीढ़ी को अधिक से अधिक सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध कराई जाएं और उनमें ऐसे संस्कार विकसित किए जाएं कि वह मूल रूप से हिंदी भाषा में काम करें।

वर्तमान समय में कोई भी भाषा सूचना प्रौद्योगिकी के बिना पल्लवित और पोषित नहीं हो सकती। राजभाषा विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राजभाषा हिंदी और अधिक प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के अभियान को आगे बढ़ाते हुए, राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिंदी के लिए ई–टूल्स सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। 'वोकल फॉर लोकल' के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में विभाग द्वारा निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' का विस्तार किया जा रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ–साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त लीला हिंदी प्रवाह, ई–महाशब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन भी हिंदी प्रेमियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। राजभाषा विभाग द्वारा ई–सरल हिंदी वाक्यकोश का विकास किया जा रहा है।

राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेषित करने में, हिंदी गृह–पत्रिकाओं का विशेष महत्व है। राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए ई–पत्रिका पुस्कालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई–पत्रिकाओं से लाभान्वित हो पाएंगे। आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरा यह कहना है कि सभी मंत्रालय सरकारी कामकाज में इन ई–टूल्स का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करें।

विगत कई माह से पूरी दुनिया अत्यंत विषम परिस्थिति से गुजर रहीं है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कोरोना महामारी से लड़ने में सफल रहा और इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्ष नागरिकों ने भी सहयोग किया है। समय–समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर देश की जनता को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। कोरोना महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित संकट की स्थिति के कारण, जनहित को प्राथमिकता देते हुए इस वर्ष 'हिंदी दिन समारोह' का आयोजन नहीं किया जा रहा है लेकिन जिन मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं, बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने पूरे वर्ष पूरी निष्ठा से हिंदी में श्रेष्ठ कार्य किया है और प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार जीते हैं, उन्हें मैं अपनी ओर से बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ–साथ हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन और पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लिए प्रदान किए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार विजेता भी बधाई के पात्र हैं ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पुरस्कार विजेता यहीं से थकेंगे नहीं, भविष्य में, हिंदी के लिए कार्य करने के लिए, उच्च और अनुकरणीय मानदंड प्रस्थापित करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी कि देश इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करे। राजभाषा विभाग ने भी इस अवसर का सकारात्मक उपयोग करते हुए सूचना तकनीक का सहारा लिया और पहली बार वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए, बड़ी संख्या में, ई–निरीक्षण एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया। राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शुरु किया गया जिसमें परंपरागत क्लास रूम टीचिंग को परिवर्तित कर, ऑनलाइन वेब कांफ्रेसिंग टूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन करें, तत्परता के साथ अनुपालन करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों से राजभाषा अधिनयमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ, निर्बाध रूप से उठा पाए।

आइए! हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हिंदी की उन्नति व प्रगति की यात्रा पूरे समर्पण के साथ हम आगे बढ़ाते हुए, हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी को सभी स्थानीय भाषाओं के साथ में रखते हुए, हिंदी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। इस मौके पर, मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि जब स्थानीय भाषा में बोलने वाला साथी हो तब और कोई भाषा का प्रयोग न करते हुए भारतीय भाषाओं के प्रयोग का आग्रह रखिए। मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, – अपने बच्चों के साथ भारतीय भाषाओं में बात करने की बात का संस्कार डालें और अपनी भाषाओं की यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति से अन्य भारतीय भाषाओं व हिंदी का समानांतर विकास होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हिंदी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु, विश्वपटल पर ज्ञान–विज्ञान से परिपूर्ण समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित होगी।

'हिंदी दिन' के शुभ अवसर पर आप सभी को पुनः मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

भारत माता की जय!

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2020

(अमित शाह)

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

सत्यमेव जयते

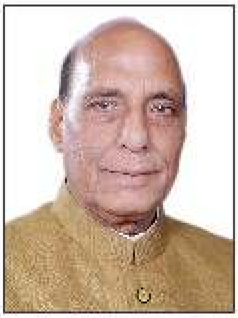

रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

संदेश

जैसा कि विदित है, हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भारत विविधताओं का देश है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तथापि, अपनी सरलता, सुबोधता और पहुंच के कारण हिंदी ने भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त किया हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और इसके बाद हिंदी ने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है तथा अनेकता में एकता की भावना को मजबूत बनाए रखा है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जनता और शासन के बीच जनभाषा ही संपर्क भाषा के रूप में सार्थक भूमिका अदा कर सकती है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभों के बारे में जनता को उनकी भाषा में अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी दी जा सकती है।

मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष कोविड–19 महामारी के बावजूद रक्षा मंत्रालय एवं अन्य सभी रक्षा संगठनों में हिंदी पखवाड़े का आयोजन मानक दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए किया जा रहा है। मैं, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं एवं सभी रक्षा संगठनों के देश भर में फैले विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे अपना अधिक से अधिक सरकारी काम–काज राजभाषा हिंदी में करते हुए संवैधानिक अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करें।

एक बार फिर से हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर रक्षा मंत्रालय, सभी सशस्त्र सेनाओं एवं अन्य रक्षा संगठनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

"जय हिन्द"

नई दिल्ली
13 सितम्बर, 2020

13.09.20

राजनाथ सिंह

राजभाषा दृष्टि
RAJBHASHA VISION

संस्थान के कार्यकलाप के हर क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी को सरल रूप में अपनाना।

To adopt Official Language Hindi in every sphere of activity of the Company in its simple form.

राजभाषा ध्येय
RAJBHASHA MISSION

प्रतिबद्धता, प्रेरणा और प्रोत्साहन द्वारा हिन्दी में मूल कार्य करने की संस्कृति को आत्मसात करना व राजभाषा हिन्दी को मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में अपनाना।

To imbibe a culture of doing original work in Hindi through Commitment, Motivation and Incentives and to adopt Rajbhasha Hindi as the spoken, written and electronic medium of communication.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

श्री एम वी गौतम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अंक-9

आशीर्वचन

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हिंदी का कामकाज बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी कंपनी को मिला 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' और हमारे राजभाषा अधिकारी श्री श्रीनिवास राव को मिला 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' इसके प्रमाण हैं। ये पुरस्कार हमें हिंदी में और बेहतर कार्य करने को प्रेरित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिलसिला बरकरार रहेगा।

कोविड–19 महामारी से जूझते हुए हमने बहुत कुछ सीखा है। हाथों को साफ करने के तरीके से लेकर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास तक, इस महामारी ने हमें जीने का नए दृष्टिकोण, नई परिभाषा, नए तौर–तरीके अपनाने को तत्पर किया है। अब जबकि हम इस जंग को आधा जीत चुके हैं और इस संक्रमण का इलाज नजदीक है, हम अपने कामकाज और जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता कोई नई अवधारणा नहीं है। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद पूरा देश एक बार फिर इसे नए सिरे से समझने और अपनाने को तैयार हो रहा है।

हर्ष का विषय है कि कार्पोरेट हिंदी पत्रिका **नवप्रभा** का नवां अंक इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रकाशित किया जा रहा है। यह अंक हमारे कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लिखे गए आत्मनिर्भर भारत संबंधी विभिन्न विषयों पर आधारित है। मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी में छपे आलेख और विचार पाठकों के लिए उपयोगी साबित होंगे।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए शुभकामनाएँ।

एम.वी. गौतम

(एम.वी. गौतम)

कार्पोरेट राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यगण

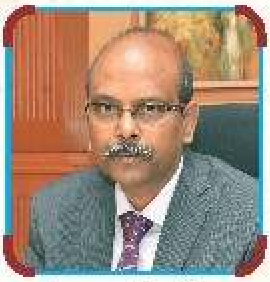

श्री एम वी गौतम
सी.एम.डी, अध्यक्ष

श्री शिवकुमारन के एम
निदेशक (एच.आर.) उपाध्यक्ष

श्रीमती रानी वर्गीस
ई.डी. (वित्त), सदस्य

श्रीमती हेमलता के
महाप्रबंधक (एस.पी.), सदस्य

श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक (एच.आर.), सदस्य

श्री के वी सुरेश कुमार
महाप्रबंधक, (टी.पी.), सदस्य

श्री रामन आर
महाप्रबंधक (आई.ए.), सदस्य

श्री मंजुनाथ डी हेगड़े
अ.म.प्र. (सतर्कता), सदस्य

श्री श्रीनिवास एस एस आर
व.उ.म.प्र. (लाइसें.), सदस्य

श्री सुरेश माइकल जी
अ.म.प्र. (एच.आर.), सहयो. सदस्य

श्री अशोक के एस
व.उ.म.प्र. (सी.सी), सदस्य

श्री मनोज यादव
व.उ.म.प्र. (एम.एस.), सदस्य

श्री श्रीनिवास एस
कंपनी सचिव, सदस्य

श्री श्रीनिवास राव
अधिकारी (रा.भा.), सदस्य सचिव

BHARAT ELECTRONICS
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

श्री शिवकुमारन के एम
निदेशक (मानव संसाधन)

उद्बोधन

प्रसन्नता का विषय है कि कार्पोरेट हिंदी पत्रिका **नवप्रभा** का नवां अंक प्रकाशित किया जा रहा है जो 'आत्मनिर्भर भारत' विषय पर आधारित है। आत्मनिर्भर भारत बनने का तात्पर्य है कि हमारे देश को हर क्षेत्र में खुद पर ही निर्भर होना होगा। देश में ही हर वस्तु का निर्माण करना होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाना है। यानी आगे चलकर हम अन्य देशों से आयात कम और निर्यात ज्यादा कर सकेंगे और अंततोगत्वा समृद्ध भारत का सपना दोबारा साकार होगा।

डिजिटल भारत का नारा भी अब सरकारी और निजी क्षेत्रों में सुर्खियों में है। इस पहल के तहत सभी प्रकार के लेन–देन से लेकर यथासंभव सभी कार्यकलाप डिजिटल ढंग से करने का लक्ष्य है। इसी प्रयास में राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी पत्रिकाओं के लिए ई–पत्रिका पुस्तकालय शुरु किया है जो स्वागत योग्य है। इस पहल का समर्थन करते हुए कार्पोरेट पत्रिका **नवप्रभा** का ई–संस्करण हमने उक्त पुस्तकालय में उपलब्ध कराया है।

गंभीर और तकनीकी विषय होने के बावजूद हमारे कर्मचारियों ने लेखन में रुचि दिखाई और इस अंक के लिए अच्छे–अच्छे लेख भेजे। मैं आशा करता हूँ कि सभी कर्मचारी और अधिकारी इस अंक को अवश्य पढ़ेंगे और राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार में अपना सहयोग देते रहेंगे। संपादन मंडल और रचनाकारों को मेरा अभिनंदन। पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हो, शुभमस्तु।

(शिवकुमारन के.एम.)

अंक–9

राजभाषा हिंदी के सरल कार्यान्वयन हेतु हम क्या करें?

- पत्रों या फाइलों में टिप्पणियाँ हिंदी भाषा में लिखें और हर पत्र या फाइल में हस्ताक्षर हिंदी भाषा में ही करें।
- राजभाषा कार्यान्वयन से संबद्ध सूचनाओं को कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाते रहें ताकि सभी कार्मिक इसके महत्व को समझ सकें।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दें। 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी आप हिंदी में दे सकते हैं।
- हिंदी में फैक्स/ ई-मेल करना आरंभ करें। अंग्रेजी में प्राप्त ई-मेल का उत्तर भी आप हिंदी में दे सकते हैं। अपने ई-मेल के व्यक्तिगत सूचना विकल्प में जाकर आप अपना नाम, पता, विभाग आदि द्विभाषा में लिखें।
- रबर की मुहरें हिंदी एवं अंग्रेजी यानी द्विभाषी बनवाएं।
- डिस्पेच रजिस्टर में डाक हिंदी में चढ़ाएं तथा हिंदी में भेजे जा रहे पत्रों के आगे H लिखें तथा अंग्रेजी में भेजे जा रहे पत्रों के सामने कॉलम में E लिखें ताकि हिंदी पत्राचार का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात हो सके।
- कार्यालय प्रभारी हिंदी में कामकाज की देखरेख करते हुए कार्मिकों को हिंदी में कामकाज के लिए पूर्ण प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करें।
- राजभाषा अनुभाग में उपलब्ध हिंदी किताबों को लेकर पढ़े। रोज कम से कम एक हिंदी शब्द सीखें तथा उसका प्रयोग जरूर करें।
- अपने विभाग से संबंधित पत्राचार में द्विभाषी प्रारूप का उपयोग करें।
- अपने वार्तालाप में सरल बोलचाल की हिंदी का प्रयोग करें।
- लिफाफों पर पता हिंदी में लिखें।

राजभाषा हिंदी अपनाएँ
देश का गौरव बढ़ाएँ

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

श्री विक्रमन एन
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

अंक-9

संबोधन

कार्पोरेट हिंदी पत्रिका **नवप्रभा** का नवां अंक आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं, नवप्रभा का हर अंक विषय–विशिष्ट होता है और समीचीन भी होता है। यह अंक भारत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व शुरु की गई महत्वपूर्ण पहल आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। हम सभी जानते हैं कि आज देश का आत्मनिर्भर बनना कितना आवश्यक बन गया है। इस अंक में आपको आत्मनिर्भर भारत से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे अर्थव्यवस्था और अवसंरचना का विकास, प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली, बढ़ती मांग, स्वरोजगार का सृजन, एमएसएमई, स्टार्टअप, उत्पादों/सेवाओं की क्षमता और गुणता में बढ़ोत्तरी, वोकल फॉर लोकल, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर रोचक और ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ने को मिलेगी।

राजभाषा कार्यान्वयन को हम पूरी गंभीरता से लेते हैं और कार्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ सभी यूनिटों और कार्यालयों में हिंदी का कामकाज निरंतर बढ़ाने का सच्चा प्रयास करते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और मुझे खुशी है कि हम इन लक्ष्यों को निरंतर प्राप्त करते आ रहे हैं। कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों में भी तय कार्यक्रम के अनुसार अधीनस्थ यूनिटों का राजभाषाई निरीक्षण करना इसका प्रमाण है। पत्रिका में अपना योगदान देने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। प्रबुद्ध पाठकों से मेरा अनुरोध है कि इस पत्रिका की गुणता बढ़ाने के लिए जो भी सुझाव उपयुक्त लगे, हमें अवश्य भेजें। हिंदी में लिखना और पढ़ना जारी रखें।

शुभकामनाओं सहित।

विक्रमन एन

(विक्रमन एन.)

बी ई एल में लागू राजभाषा प्रोत्साहन योजनाएं

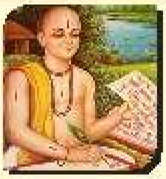

तुलसीदास पुरस्कार योजना
सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करने के लिए पुरस्कार योजना

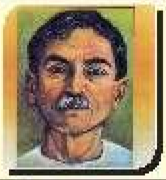

प्रेमचंद पुरस्कार योजना
हिन्दी में कार्य करने के लिए कार्यपालकों तथा गैर–कार्यपालकों के लिए अलग अलग पुरस्कार योजना

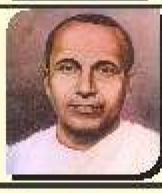

जयशंकर प्रसाद पुरस्कार योजना
कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार योजना

कबीर पुरस्कार योजना
प्रेरणा देने वाले ऐसे उच्चाधिकारियों के लिए पुरस्कार जो हिन्दी में पृष्ठांकन/ हस्ताक्षर/ टिप्पणी लिखते हैं और अपने प्रभाग/ विभाग में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं

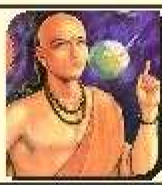

भास्कराचार्य पुरस्कार योजना
हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए

नागार्जुन पुरस्कार योजना
हिन्दी में तकनीकी लेख लिखने के लिए

निराला पुरस्कार योजना
हिन्दी में व्याख्यान देने/ सत्र चलाने को प्रोत्साहित करने के लिए

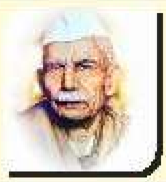

माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार योजना
हिन्दी माध्यम के साथ कक्षा X/ XII/ डिग्री/ डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर स्तर में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार

मैथिलीशरण पुरस्कार योजना
कक्षा X / XII / डिग्री/ डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर स्तर में प्रथम/ द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी में सर्वोच्च अंक अर्जित करने के लिए पुरस्कार

बीईएल के राजभाषा अधिकारीगण

श्रीनिवास राव
कार्पोरेट कार्यालय

रजनी साव
कार्पोरेट कार्यालय

एच एल गोपालकृष्णा
बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स

बी. सुरेश कुमार
हैदराबाद

बिमल मोहन सिंह रावत
नवी मुंबई/पुणे

श्यामलाल दास
चेन्नै

नवजोत पीटर
गाजियाबाद,
सीआरएल–गा.बाद

माधुरी रावत
कोटद्वार

भूपेन्द्र सिंह
पंचकूला

दिनेश उईके
मछिलिपट्टनम

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कार्पोरेट कार्यालय

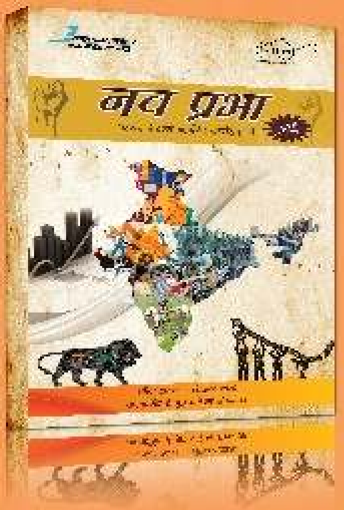

नव प्रभा अंक–09
अर्धवार्षिक गृह पत्रिका
(केवल निजी वितरण के लिए)

मार्गदर्शन
श्री के. एम. शिव कुमारन
निदेशक (मानव संसाधन)

संरक्षक
श्री विक्रमन एन.
महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

परामर्शदाता
श्री सुरेश माइकल
अपर महाप्रबंधक (मा.सं.–नीति व क.सं.)

संपादक
श्री श्रीनिवास राव
अधिकारी (राजभाषा)

सुश्री रजनी राव
वरिष्ठ सहायक अधिकारी (राजभाषा)

सहयोग
सुश्री रहिला राज के एम
कनिष्ठ अनुवादक

(पत्रिका में प्रकाशित रचनाएं लेखकों के निजी विचार हैं, बीईएल से इसकी सहमति अनिवार्य नहीं है)

BHARAT ELECTRONICS

संपादकीय

सुधि पाठकों,

आपको नव प्रभा का नवां अंक सौंपते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। नव प्रभा का प्रत्येक अंक वैविध्यपूर्ण विषयों पर आधारित्त होता है और आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह अंक ई–पत्रिका के रूप में प्रकाशित की गई है। यह नवीनतम अंक आत्मनिर्भर भारत पहल से संबंधित जानकारियों, विशेषताओं और उसके आधार स्तंभों पर आधारित है।

आज जब पूरा संसार वैश्विक महामारी की चपेट में है तब नई चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हैं। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य सिर्फ कोविड–19 महामारी के दुष्प्रभाव से लड़ना नहीं बल्कि भविष्य में भारत का पुर्ननिमार्ण करना भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अब एक नई प्राणशक्ति, नई संकल्पशक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत में स्वदेशी को एक विचार के रूप में देखा जाता है जिसने भारत की आजादी में भी एक अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। कोविड–19 से लड़ते हुए हमने नई चुनौतियों का सामना किया है और इस परिस्थिति में बहुत कुछ सीखा भी है।

यह अंक आत्मनिर्भर भारत के नवीनतम पहलुओं को आपके समक्ष रखने का एक प्रयास मात्र है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आवश्यक मुख्य स्तंभों की जानकारियां कई रोचक और ज्ञानवर्धक रचनाओं के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है जो आपको अवश्य पसंद आएगी।

इस अंक को मूर्त रूप देने में हमारे रचनाकारों की बड़ी भूमिका रही है जिन्होंने आर्थिक व्यवस्था, जनसांख्यिकी, औद्योगिक व्यवस्था आदि जैसे गंभीर विषयों पर अद्यतन जानकारियां देते हुए हमें सुंदर लेख उपलब्ध कराएं हैं। मेरी ओर से सभी रचनाकारों को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद।

आपकी स्नेहवत प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।

वरिष्ठ सहायक अधिकारी (राजभाषा)

हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा के पथ की ओर अग्रसर

हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा, राष्ट्रीय एकता का अभिन्न अंग है और यह देश की जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम शक्तिशाली तथा प्रभावशाली माध्यम है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद हिंदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को मजबूत किया है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान जार्ज गियर्सन ने कहा था कि – **"हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्टकार्ड पर लिखे जा सकते हैं"।**

सरल होने के साथ हिंदी भाषा जितनी वैज्ञानिक कोई और भाषा इस विश्व में नहीं है। हिंदी के इसी गुण और महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने इसे सन 1949 को संघ सरकार की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया । 'राजभाषा' का शाब्दिक अर्थ है– राजकाज की भाषा। दूसरे शब्दों में जिस भाषा के द्वारा राजकीय कार्य संपादित किए जाएँ वही 'राजभाषा' कहलाती है। आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने 'राजभाषा' को परिभाषित करते हुए कहा है– **'राजभाषा उसे कहते हैं जो केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र– व्यवहार, राजकाज और सरकारी लिखा–पढ़ी के काम में लाई जाए।'**

राजभाषा सरकार और आम जनता के बीच परस्पर संवाद कायम करती है। परंतु जब भाषा का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत होकर समस्त राष्ट्र में व्याप्त हो जाता है तब वह भाषा 'राष्ट्रभाषा' बनती है। 'राष्ट्रभाषा'का सीधा अर्थ है राष्ट्र की वह भाषा, जिसके माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं सम्पर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लाँघकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जन मानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। राष्ट्रभाषा में समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना का संवहन करने की अतिरिक्त क्षमता होती है ।

हिंदी को भले ही औपचारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित न किया गया हो परंतु ग्यारहवीं शताब्दी से ही हिंदी अक्षुण्ण रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी सरीखे राष्ट्र–पुरुषों ने हिंदी के ही जरिए समूचे राष्ट्र से संपर्क किया ।20 अप्रैल 1935 को इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गाँधी ने भारत की राष्ट्रभाषा के संबंध में कहा था –**'अंग्रेजी कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता'।**

आधुनिक काल में हिंदी भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बन गई है। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो या स्वाधीनता संग्राम का, हर जगह हिंदी ही जनता के विचार–विनिमय का माध्यम बनी। हिंदी के दैनिक सरकारी उपयोग ने कर्मचारियों तथा उनसे जुड़ें अन्य लोगों को भी हिंदी की ओर आकर्षित किया हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी भी भारत आगमन पर भारतीय संस्कृत व हिंदी की ओर आकर्षित होते हैं व भारतीय संस्कृति को अपना कर हिंदी सीखते व बोलते है।

साहित्य का भी हिंदी को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के पत्रका रिता क्षेत्र ने भी हिंदी प्रयोग में व्यापक रूप से तेजी दिखाई है। समाचारपत्र पंजीयन कार्यालय, नई दिल्ली की वेबसाइट पर वर्तमान में उपलब्ध 2017–18 के आंकड़ों के अनुसार, कुल पंजीकृत प्रकाशनों की संख्या 1,18,239 थी जिसमें से सबसे अधिक 47,989 प्रकाशन हिंदी भाषा के थे। वहीं पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सर्वाधिक पंजीकृत कार्यालयों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। समाचार पत्रों के सभी संस्करण सभी सामाजिक मीडिया मंचों पर हिंदी में उपलब्ध हैं। एक्सचेंज फॉर मीडिया डॉट कॉम के अनुसार 2019 की प्रथम तिमाही में हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय समाचार पत्र अकेले दैनिक जागरण ने 7 करोड़ से अधिक प्रतियाँ छापी। इस सूची में कई बड़े नाम भी है जिन्होंने अपने कीर्तिमान स्वयं तोड़े । उन्नत नवीन प्रौद्योगिकी भी हिंदी के उपयोग में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सामाजिक मीडिया पर हिंदी साहित्य से संबंधित कई नई वेबसाइट बन गई हैं। बाजार में निवेशकों ने हिंदी भाषियों के विभव का आकलन कर उसे

गहराई से समझ लिया है। अधिकतर उत्पाद चाहे वे किसी भी रूप में हो, उनकी जानकारी हिंदी भाषियों को हिंदी में उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के लिए बीमा योजनाएं, बैंकिंग योजनाएं, उपभोगी वस्तुएँ व उनके विज्ञापन आदि। कौन सी भाषा किस प्रकार व किस समय एक विशाल वृक्ष के समान धरा पर छा जाएगी कोई नहीं जानता। यह भी निश्चित नहीं है कि आज से कुछ वर्ष बाद भाषा का स्वरूप क्या होगा परंतु उपरोक्त उदाहरणों को देख कर यह स्पष्ट है कि भारत में भीतर ही भीतर हिंदी भाषा की मजबूत जड़ों का विकास हो रहा है। शिवपूजन सहाय ने सही कहा है – **"भारतेन्दु और द्विवेदी ने हिंदी की जड़ पाताल तक पहुँचा दी है, उसे उखाड़ने का जो दुस्साहस करेगा वह निश्चय ही भूकंपध्वस्थ होगा।"**

वर्तमान समाज का दायित्व राजभाषा हिंदी की शब्द सम्पदा को सुंदर व मजबूत बनाकर उसे राष्ट्रभाषा बनाना है जिससे वह भारत सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति सहजता और दृढ़ता से कर सके। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कभी कहा था – **भाषा का निर्माण सेक्रेट्रिएट में नहीं होता,भाषा गढ़ी जाती है जनता की जिह्वा पर।**

नकुल गोयल, कनिष्ठ सहायक
गाजियाबाद

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की सूची

हिंदी – 1950	ओड़िया – 1950	संस्कृत – 1950	बोड़ो – 2004
असमिया – 1950	तमिल – 1950	मराठी – 1967	डोगरी – 2004
बंगला – 1950	मलयालम – 1950	सिन्धी – 1992	मैथिली – 2004
गुजराती – 1950	तेलुगू – 1950	कोंकणी – 1992	संथाली – 2004
कश्मीरी – 1950	उर्दू – 1950	मणिपुरी – 1992	
कन्नड़ – 1950	पंजाबी – 1950	नेपाली – 1992	

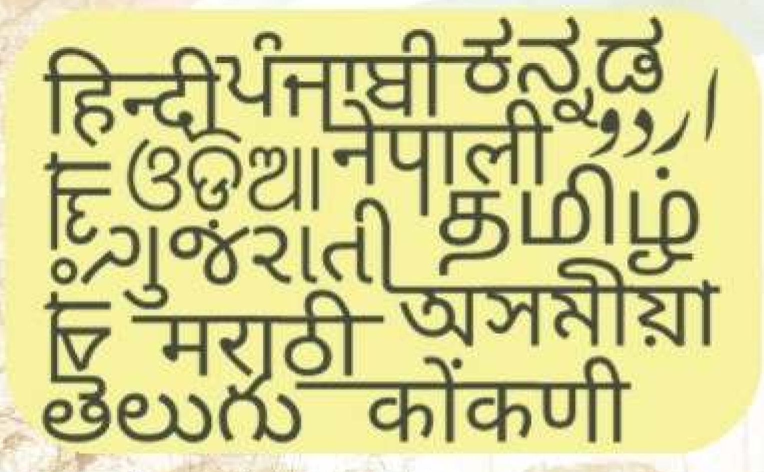

याद रखने योग्य बातें

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाने चाहिए -

☞ सामान्य आदेश/परिपत्र / ज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पणियाँ, संविदाएँ, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म/ नोटिस, अधिसूचनाएं, संकल्प, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट

The following documents which come under section 3(3) of OL Act must be issued in bilingual: General Orders/Circulars/Memo, Press Communiques/Releases, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Tender Forms/ Notices, Notification, Resolutions, Administrative and other Reports.

☞ हिंदी में प्राप्त पत्रों के जवाब हिंदी में ही दें।
Replies to the letters received in Hindi may be replied to in Hindi.

☞ सभी लेखन सामग्रियाँ, प्रपत्र और प्रारूप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होने चाहिए।
All stationery items, forms and formats should be in Hindi and in English.

☞ सभी रबड़ की मोहरें, विज़िटिंग कार्ड हिंदी में भी होने आवश्यक हैं।
All Rubber Stamps, Visiting Cards must be in Hindi also.

☞ साइन बोर्ड, होर्डिंग, बैनर जैसी मदें क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी के क्रम में होने चाहिए।
Sign Boards, Hoarding, Banners etc. may be prepared in Regional Language, Hindi and in English respectively.

☞ केन्द्र सरकार के कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की होती है।
The onus of OL implementation lies on the Administrative Head of the Central Govt. Office.

☞ 'ग' क्षेत्र में होने के नाते हिंदी / द्विभाषी पत्राचार का हमारा लक्ष्य (न्यूनतम) **55% है** ।
Being in 'C' region, our target (minimum) for Hindi / Bilingual correspondence is 55%.

☞ 'ग' क्षेत्र में होने के नाते हिंदी / द्विभाषी टिप्पणी लिखने के लिए हमारा लक्ष्य (न्यूनतम) **30% है** ।
Being in 'C' region, our target (minimum) for Hindi/Bilingual notings is 30%.

☞ सभी कंप्यूटरों / लैपटॉप में हिंदी में कार्य करने के लिए यूनिकोड सक्रिय होना चाहिए।
All PCs / Laptops should be Unicode enabled to work in Hindi.

बीईएल कार्पोरेट कार्यालय को दो सर्वोच्च सम्मान राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार

वर्ष 2019—20 के दौरान राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी के अंतर्गत 'ग' क्षेत्र में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कार्पोरेट कार्यालय को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। सचिव, राजभाषा विभाग ने इसके लिए सीएमडी, बीईएल को हिंदी के प्रयोग व प्रसार की दिशा में किए गए सफल सद्प्रयासों के लिए राजभाषा विभाग को हार्दिक बधाई प्रेषित की। वर्ष 2018—19 के दौरान राजभाषा गौरव पुरस्कारों के अंतर्गत हिंदीतर भाषी क्षेत्र के लिए श्री श्रीनिवास राव, अधिकारी (राजभाषा), बीईएल कार्पोरेट कार्यालय को उनके लेख "भारतीय विज्ञापन जगत – आकार, विकास, संभावनाएँ और भविष्य" को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार स्वरूप उन्हें नकद राशि, प्रशस्ति—पत्र और स्मृति—चिह्न प्रदान किए जाएँगे। ये पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में माननीय राष्ट्रपति जी के कर—कमलों से प्रदान किए जाएँगे ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 04.09.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। लोक सभा और राज्य सभा के कुल 9 संसदीय सदस्यों ने प्रश्नावली की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 14.10.2020 को केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाजियाबाद का राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। लोक सभा और राज्य सभा के कुल 7 संसद सदस्यों ने प्रश्नावली की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाजियाबाद के मुख्य वैज्ञानिक, वरिष्ठ अधिकारियों और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय से संयुक्त सचिव (एरो) तथा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों ने भाग लिया। समिति ने केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाजियाबाद में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतुष्टि व्यक्त की।

नराकास (उपक्रम) बेंगलूरु के तत्वावधान में आयोजित ई-संगोष्ठी

दिनांक 08.07.2020 को बीईएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा नराकास (उपक्रम), बेंगलूरु के तत्वावधान में "कोरोना के बाद की सभ्यता और भाषा" विषय पर गूगल मीट द्वारा एक ई-संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रो. रजनीश कुमार शुक्ल, कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) ने इस संगोष्ठी में अपना व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में नराकास (उपक्रम), बेंगलूरु के विभिन्न सदस्य पीएसयू के कुल 46 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

नराकास (उ) के तत्वावधान में ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन

दिनांक 18 अगस्त, 2020 को बीईएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु के तत्वावधान में आयोजित संयुक्त हिंदी माह प्रतियोगिता – 2020 के अंतर्गत गूगल मीट द्वारा ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इस प्रतियोगिता में बेंगलूरु स्थित विभिन्न पीएसयू के 32 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के निर्णायक श्री अशोक कुमार बिल्लुरे, संयुक्त निदेशक (से.नि.)/राजभाषा, इसरो, वर्तमान में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के सदस्य तथा श्री ईश्वर चंद्र मिश्र, सहायक निदेशक (से.नि.), केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय थे।

ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण

दिनांक 18 सितंबर, 2020 को केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग के तत्वावधान में ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण (गूगल मीट द्वारा) कार्यशाला का आयोजन कार्पोरेट राजभाषा द्वारा किया गया। संपूर्ण बीईएल के राजभाषा अधिकारियों/अनुवादकों सहित कुल 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन श्रीमती जानकी नायर, संयुक्त निदेशक (सी.टी.बी.), राजभाषा विभाग ने किया।

देश की सेवा मेरी भक्ति है, हिंदी भाषा मेरी शक्ति है।

राष्ट्रीय अनुवाद प्रतियोगिता विजेता

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त 2020 के दौरान ऑनलाइन अनुवाद प्रतियोगिता यानी स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अनुवाद के ग्लोबल डेटा बेस को सशक्त बनाना था ताकि उपयोगकर्ता इस टूल से लाभान्वित हो सकें। इस प्रतियोगिता में भारत भर से चुने गए सर्वोच्च 10 अनुवादकों को सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति–पत्र दिया गया। श्री श्रीनिवास राव, अधिकारी (राजभाषा), बीईएल–कार्पोरेट कार्यालय सर्वोच्च दस स्थान पर रहे और उन्हें सचिव (राजभाषा), भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति–पत्र सीएमडी महोदय ने प्रदान किया। इसके अलावा सचिव (राजभाषा), भारत सरकार ने हमारे सीएमडी महोदय को भी प्रशस्ति–पत्र प्रेषित किया। डॉ सुमित जैरथ, सचिव, (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 21.09.2020 को आयोजित कार्यक्रम में उनसे व्यक्तिश: बातचीत की और उनके सफल प्रयास के लिए बधाई दी।

कार्पोरेट कार्यालय में हिंदी माह का आयोजन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी हिंदी दिवस के आयोजन संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुपालन के साथ सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्पोरेट कार्यालय में हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी माह 2020 के पहले कार्य दिवस पर सीएमडी महोदय द्वारा जारी संदेश का परिचालन किया गया और मानक द्विभाषी ईमेल का संकलन सभी कार्यपालकों को मेल द्वारा भेजा गया। इस दिन सभी उच्चाधिकारियों के लिए सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन उनके कार्य स्थल पर किया गया जिसमें कुल 33 उप महाप्रबंधक सहित महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। पूरे माह के दौरान स्वागत कक्ष में राजभाषा विभाग से प्राप्त महान विभूतियों के हिंदी की सूक्तियाँ और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। कार्पोरेट कार्यालय के बाहर संयुक्त हिंदी माह, नराकास और कंपनी की हिंदी माह के बैनर प्रदर्शित किए गए। विशेष पहल के रूप में इस वर्ष कर्मचारियों के परिवार और बच्चों के लिए ऑनलाइन अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके साथ ही प्रशासनिक शब्दावली, पीसी पर हिंदी टंकण, नारा लेखन, सही शब्द क्या है? और राजभाषा हिंदी और क्षेत्रीय भाषा कन्नड़ का मेल करते हुए एक नई प्रतियोगिता हिंदी कन्नड़ संगम सहित कुल सात प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में कुल 71 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया जिसमें से 27 लोगों ने पुरस्कार प्राप्त किए। हिंदी का प्रचार–प्रसार कार्यालय से बाहर भी हो, इसलिए बीईएल सीबीएसई स्कूल की नवीं और दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। हिंदी दिवस के अवसर पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सीएमडी महोदय के संदेश पढ़े गए। इस अवसर पर सीएमडी और निदेशकगण सहित सीवीओ और सभी महाप्रबंधक उपस्थित थे। शेष अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय के सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम) द्वारा इन संदेशों का प्रसारण किया गया। 28 सितंबर को कार्पोरेट राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। दिनांक 30 सितंबर को 'गांधी की विचारधारा', 'हास्य चिकित्सा' और 'हिंदी भाषा' पर वीडियो स्क्रीनिंग की गई जिसे 32 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने देखा।

हिंदी माह समारोह की झलकियां

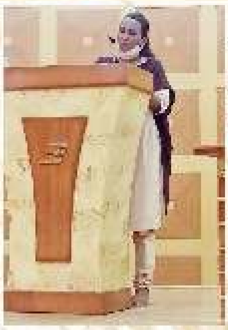

"राजभाषा कार्यान्वयन – महत्वपूर्ण पहलू" पर ई–कार्यशाला

दिनांक 20 मई 2020 को **"राजभाषा कार्यान्वयन – महत्वपूर्ण पहलू"** विषय पर ई–हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 20 अधिकारियों ने भाग लिया। सभी नामित प्रतिभागियों को पहले पीपीटी सामग्री अध्ययन के लिए उनके ईमेल पर भेजी गई। सामग्री का अध्ययन करने के बाद अगले दिन यानी 21 मई, 2020 को ईमेल द्वारा कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भेजे गए जिनमें सही उत्तर को कलर कोड देकर या सही चिह्न लगाकर कार्पोरेट राजभाषा को भेजा गया। दिनांक 28 मई, 2020 को कार्पोरेट कार्यालय के गैर–कार्यपालकों के लिए इसी विषय पर एक दूसरी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 20 गैर–कार्यपालकों ने हिस्सा लिया।

कर्मचारियों के परिजनों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता

हिंदी माह आयोजन के दौरान अभिनव पहल के रूप में इस वर्ष बीईएल कार्पोरेट कार्यालय के परिजनों के लिए ऑनलाइन अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता का आनंद उठाया। इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों के परिवार और बच्चों में हिंदी के प्रति उत्साह और रूचि जागृत करना था।

इसके अलावा, बीईएल सीबीएसई स्कूल की नवीं और दसवीं कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन आशुभाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई।

हिंदी वीडियो स्क्रीनिंग

दिनांक 19.06.2020 को 'योग द्वारा श्वसन– संबंधी व्याधियों की रोकथाम' विषय पर हिंदी वीडियो स्क्रीनिंग की गई जिसमें समाजिक दूरी का पालन करते हुए दो सत्रों में 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और आयुर्वेद औषधियों की जानकारियों के साथ – साथ फल–सब्जियों के सेवन द्वारा रोगमुक्त रहने की जानकारियाँ प्राप्त की। दिनांक 30 सितंबर को 'गांधी की विचारधारा', 'हास्य चिकित्सा' और हिंदी भाषा पर वीडियो स्क्रीनिंग की गई जिसे 32 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने देखा और अभ्यास किया।

यदि तुम भूलों को रोकने के लिए द्वार बंद कर दोगे
तो सत्य भी बाहर रह जाएगा।

– रवींद्रनाथ ठाकुर

यूनिटों और कार्यालयों की राजभाषा गतिविधियाँ

आसानी से हिंदी सीखें

- इसके लिए आपको एक सवाल का जवाब देना होगा, क्या आप तैरना सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आपको पानी के संपर्क में रहना पड़ेगा, उसमें डूबना, उतरना और हाथ पैर मारना सीखना होगा, तभी आप तैरना सीख सकेंगे, यही इस दुनिया में कुछ भी सीखने के सम्बन्ध में सच है।
- किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसे पढ़ना, सुनना और व्यवहार में लाने का प्रयास करते रहना होगा।
- आप हिंदी समाचार, पत्रिका, टीवी प्रोग्राम देखिए, सुनिए और खुद हिंदी लिखने–बोलने का प्रयास करते रहिए। ऐसे लोगो की संगत में रहिए जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हो, कुछ समय बाद आप भी उन सभी की तरह हिंदी बोलना, लिखना सीख जाएंगे । इसे आज से ही शुरू कर दीजिए।
- हिंदी की वैसी पुस्तक पढ़ें, जो जीवन के हर क्षेत्र का स्पर्श करती है। बार–बार पढ़ें।
- किसी भी भाषा को सीखने से पहले यदि बेसिक स्पष्ट हों तो कोई भी समस्या नहीं आती है। अतः बिना किसी झिझक के प्राइमरी शिक्षक से उच्चारण सीख लें, मात्राओं का तरीका देख लें, बस हिंदी सीख लेंगे।
- हिंदी में डब इंग्लिश फिल्में देखिए। आप बहुत कुछ सीख पाएंगे डब फिल्मों से।
- हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में कुछ दिन रहिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, हिंदी सीख जाएंगे।
- छोटी–छोटी कहानियों की हिंदी किताबें पढ़ना शुरू करें।
- नोटबुक बनाएं और प्रतिदिन उपयोग में आने वाले हिंदी शब्दों व वाक्यों को नोट करें और प्रयोग करें।
- पसंदीदा हिंदी गाने सुनिए और उन्हें गुनगुनाए।

बेंगलूरु कॉम्प्लेक्स में हिंदी दिवस समारोह

14 सितंबर 2020 को बीईएल के प्रबंधन भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम (राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता–2019) स्नातकोत्तर शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय, एम ई जी एवं केंद्रीय बेंगलूरु थी। डॉ विनय कुमार कत्याल, निदेशक (बेंगलूरु यूनिट) ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री चिन्नराजा राइ, अपर महाप्रबंधक (मा सं) भी उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।

ईश वंदना के पश्चात माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह जी तथा माननीय रक्षामंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी का संदेश पढ़ा गया। मुख्य अतिथि श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम ने बीईएल की राष्ट्र के प्रति भूमिका को सराहा और हिंदी के प्रति समर्पित भाव पर प्रसन्नता की। उन्होंने बताया कि हिंदी बहुत ही सरल तथा सहज भाषा है तथा उसे बहुत आसानी से समझा और समझाया जा सकता है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक, बेंगलूर यूनिट ने बताया कि किस प्रकार हिंदी संपर्क भाषा के रूप में हमें आपस में एक–दूसरे से जोड़ रही है। राजभाषा के प्रचार–प्रसार के साथ बीईएल में हिंदी में कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाना प्रशंसनीय है। इस अवसर पर राजभाषा पत्रिका सुरभि के 14वे अंक का लोकार्पण किया गया। सुरभि के लेखकों को स्मृतिचिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्रीमती शिवाली राय ने कार्यक्रम का सुचारु रूप से संचालन किया। राष्ट्र गीत के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

हैदराबाद यूनिट की राजभाषा गतिविधियाँ

- नराकास (उपक्रम) के तत्वावधान में सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में बीईएल हैदराबाद यूनिट से 02 कर्मचारियों को शब्दावली एवं अनुवाद प्रतियोगिताओं के लिए नामित किया गया।
- हिंदी माह के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हिंदी टंकण, स्लोगन टिप्पण व आलेखन और ऑनलाइन टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 82 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
- दिनांक 14.09.2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ऑनलाइन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सहित सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यस्थल से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री और सीएमडी, बीईएल द्वारा हिंदी दिवस पर जारी संदेशों को पढ़ा गया। दिनांक 30.09.2020 को हिंदी माह के कार्यक्रमों पर चर्चा एवं समीक्षा हेतु महाप्रबंधक की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

- **पुरस्कार वितरण समारोह** – कर्मचारियों द्वारा मूल रूप से हिंदी में कार्य करने की प्रोत्साहन योजना में 3 कर्मचारियों को प्रेमचंद पुरस्कार, 10 को जयशंकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के बच्चों को हिंदी विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनिट के 01 कर्मचारी के बच्चों को मैथिलीशरण पुरस्कार प्रदान किया गया। 30.09.2020 को हिंदी माह समापन समारोह में महाप्रबंधक, प्रभाग प्रधान एवं पुरस्कार विजेताओं को आमंत्रित किया गया। समारोह के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र वितरित किए गए। राजभाषा अधिकारी ने राजभाषा कार्यान्वयन गतिविधियों से कर्मचारियों को अवगत कराया और हिंदी माह कार्यक्रमों का ब्योरा दिया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयासों की सराहना की और पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी।
- **हिंदी कार्यशालाएं**– प्रथम तिमाही के दौरान दि.13.06.2020 को सामाजिक दूरी एवं सभी सुरक्षा प्रावधानों का ध्यान रखते हुए श्री वी वेंकटेश्वर राव, स.म.प्र. (रा.भा.), से.नि., सिंडिकेट बैंक के संचालन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दूसरी तिमाही में दिनांक 26.09.2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से पूर्ण दिवसीय ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री वी रविचंद्र राव, प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, हैदराबाद इस कार्यशाला के संचालक थे जिसमें कुल 60 कर्मचारियों ने भाग लिया।

चेन्नै यूनिट की राजभाषा गतिविधियाँ

हिंदी दिवस कार्यक्रम में महाप्रबंधक सहित सभी विभागीय प्रमुख एवं हिंदी माह समिति सदस्य

सितंबर माह के पहले दिन से यूनिट परिसर के अंदर और प्रवेश द्वार पर हिंदी माह बैनर प्रदर्शित किए गए। 14 सितंबर, 2020 को हिंदी दिवस तथा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक (यूनिट प्रमुख) सहित कार्यालय के सभी विभागीय प्रमुख एवं हिंदी माह समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में श्री श्यामलाल दास, अधिकारी (राजभाषा) ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा माननीय रक्षामंत्री, गृहमंत्री एवं बीईएल के सीएमडी का हिंदी दिवस पर जारी संदेश पाठ किया गया। श्री जी एल पेड्रो, महाप्रबंधक (चेन्नै) ने कहा कि इस वर्ष कोविड–19 महामारी के बावजूद कर्मचारियों ने अधिक संख्या में ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। साथ ही प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाई गई जिसमें सभी अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाओं में उपस्थित हुए। सभी विभागीय प्रमुखों को कोरोना महामारी के समय में कार्मिकों को हिंदी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु धन्यवाद व्यक्त किया। माह के दौरान कार्यालय में विभिन्न ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिताएँ जैसे– निबंध लेखन, अनुवाद, कार्यालयीन शब्दावली, हिंदी वाक्य बनाना, एवं समानार्थी व विलोम शब्द लेखन प्रतियोगिता आयोजित किए गए। प्रतियोगिता में कुल 66 अधिकारियों /कर्मचारियों ने भाग लिया। माह के दौरान हिंदी वाक्य गठन एवं अनुवाद विषयों पर ऑनलाइन हिंदी कार्यशालाएँ चलाई गई।

ऑनलाइन प्रबोध हिंदी कक्षा

ऑनलाइन प्रवीण हिंदी कक्षा

ऑनलाइन प्राज्ञ हिंदी कक्षा

गाजियाबाद यूनिट की राजभाषा गतिविधियाँ

यूनिट में 02.06.2020 को कार्मिकों के लिए राजभाषा नीति–नियम' पर ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 07.08.2020 को नराकास के तत्वावधान में बीईएल गाजियाबाद के सौजन्य से देशभक्ति गीतों पर आधारित गायन प्रतियोगिता (ऑनलाइन) का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस का शुभारंभ कार्यपालक निदेशक (एनसीएस) व यूनिट प्रमुख श्री जयदीप मजूमदार, महाप्रबंधक (रेडार) श्री जगदीश चन्द्र, महाप्रबंधक (एससीसीएस), सुश्री रुचि गर्ग, एजीएम (एंटेना), श्री संजय श्रीवास्तव, एजीएम (डीसीसीएस), सुश्री अनीता मिलिंद द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मा. सं. व प्रशा. प्रमुख श्री दिव्येंदु बिद्यांत भी उपस्थित थे।

ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन

कार्यपालक निदेशक (एनसीएस) व यूनिट प्रमुख श्री जयदीप मजूमदार द्वारा हिंदी गृहपत्रिका सृजनी के चौथे अंक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उच्चाधिकारी गण के साथ राजभाषा टीम उपस्थित थी।

कार्यपालक निदेशक (एनसीएस) व यूनिट प्रमुख श्री जयदीप मजूमदार "एंटेना एसबीयू" के प्रभारी अपर महाप्रबंधक श्री संजय श्रीवास्तव व उनकी टीम को 2019–20 हेतु हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजभाषा शील्ड प्रदान करते हुए।

मछिलिपट्टनम यूनिट की राजभाषा गतिविधियां

मछिलिपट्टनम में 14 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए हिंदी दिवस वी.सी. के माध्यम से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री दिनेश उईके, सदस्य सचिव (राभाकास) ने किया जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हिंदी दिवस पर जारी संदेश सभी कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया और बीईएल को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में भी अवगत कराया। सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने को कहा गया। राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी माह के दौरान हिंदी निबंध, हिंदी टंकण, हिंदी नारा–लेखन/पोस्टर, हिंदी प्रश्नोत्तरी और हिंदी वाचन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

हिंदी कार्यशालाएं

19.09.2020 को वेबिनार के माध्यम से हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के प्रशिक्षक श्री रविचंद्र राव, प्राध्यापक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय थे। इस कार्यशाला में कुल 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 18.09.2020 को कार्पोरेट कार्यालय द्वारा आयोजित हिंदी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम में 4 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिंदी माह पुरस्कार वितरण समारोह

29.09.2020 को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम दो सत्रों में आयोजित किया गया जिसमें हिंदी प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को प्रमाण–पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर श्री पंकज पचनंदा, कमांडेंट (सेनापति) केंद्रीय आयुध भंडार, आगरा वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी को हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया।

दूसरे सत्र में मुख्य अतिथि श्री.बी.के स्वैन, वैज्ञानिक (एसक्यूएई) आमंत्रित थे। उन्होंने यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन गतिविधियों की सराहना की। श्री बी प्रभाकर, महाप्रबंधक ने सभी कर्मचारियों को हस्ताक्षर, नोटिंग, मेल हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजभाषा अधिकारी, श्री दिनेश उईके ने हिंदी का उपयोग करने और हिंदी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने का निवेदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

पुणे यूनिट की राजभाषा गतिविधियां

यूनिट में 1 से 30 सितंबर तक 'हिंदी माह' समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यूनिट के प्रमुख स्थलों पर हिंदी माह समारोह एवं लेखकों के हिंदी प्रचार संबंधी सूक्तियों के बैनर प्रदर्शित किए गए। समारोह में अधिक से अधिक कर्मचारियों को राजभाषा गतिविधियों से जोड़ने तथा सहज आयोजन हेतु हिंदी माह आयोजन समिति गठित की गई। 07 सितंबर को हिंदी तथा हिंदीतर भाषियों के लिए 'कोविड–19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव' विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा 'हिंदी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग' प्रतियोगिता आयोजित की गई। 14.09.2020 को यूनिट के समागार में "हिंदी दिवस" समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक द्वारा दीप प्रदीपन से किया गया। तत्पश्चात "हिंदी दिवस" पर माननीय गृहमंत्री जी, रक्षामंत्री जी और सीएमडी के संदेश पढ़े गए। महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें दो राय नहीं है कि देश में अन्य भाषा भाषियों के बीच संपर्क के लिए हिंदी ही एक मात्र संपर्क भाषा है। देश के अधिकांश भू भाग में हिंदी बोली जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों सहित निदेशक स्तर पर भी हिंदी में टिप्पणियाँ लिखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पत्राचार में हिंदी ई–मेल भी शामिल किया जाए ताकि पत्राचार का लक्ष्य भी पूरा किया जा सके। कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री बी.एम.एस. रावत ने किया।

17.09.2020 को हिंदी और हिंदीतर भाषियों के लिए "राजभाषा ज्ञान व अनुवाद कौशल" प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें कार्यालयीन प्रयोग की भाषा, पारिभाषिक शब्द, राजभाषा नीति, रोजमर्रा के कार्यों में प्रयुक्त शब्द एवं मुहावरे, लघु अनुवाद पर आधारित प्रश्न शामिल किए गए। कर्मचारियों से वर्ष 2019–20 में किए गए हिंदी कार्य की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई। यह प्रतियोगिता ऐसे कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई थी जो प्रोत्साहन योजनाओं में भाग नहीं ले पाए थे। सभी 22 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। 21.09.2020 को अप्रेंटिसेस तथा संविदा लिपिकों के लिए 'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता' आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुल 42 अप्रेंटिस/संविदा लिपिकों ने भाग लिया।

25.09.2020 को प्रबंधक तथा उनसे ऊपर की श्रेणी के उच्चाधिकारियों के लिए 'राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता' आयोजित की गई। 30.09.2020 को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एच.आर.डी के खुले प्रांगण तथा एच.आर.डी. हॉल में 02 चरणों में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। अपर महाप्रबंधक (उत्पादन) तथा महाप्रबंधक द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

पंचकूला यूनिट में हिंदी माह समारोह का आयोजन

अगस्त के अंतिम सप्ताह में राभाकास की बैठक बुलाई गई और हिंदी माह के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई एवं निर्णय लिया गया कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। यूनिट में पूरे माह डिजिटल स्क्रीन पर आयोजित होने वाली हिंदी माह प्रतियोगिताओं की सूचना व हिंदी के विषय में महान हस्तियों के विचारों की विस्तृत पीपीटी बनाकर प्रदर्शित की गई। मानव संसाधन सभागार में 100 से अधिक स्थाई फ्रेम लगाए गए जिनमें महान हस्तियों की तस्वीरें व उनकी प्रेरक सूक्तियाँ प्रदर्शित की गईं। इसके अलावा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कुल 7 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा राजभाषा के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु संकल्प व्यक्त किया। हिंदी भाषा के प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से 25000 रु. की हिंदी पुस्तकों का वितरण प्रतिभागियों को किया गया।

14.09.2020 को आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब एवं सिंध बैंक के सेवानिवृत्त अपर महाप्रबंधक, श्री राजिंदर सिंह बेवली शामिल हुए। श्री बेवली ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति को उत्कृष्ट बनाने के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने बीईएल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा कीर्ति पुरस्कार व राजभाषा गौरव पुरस्कार जीतने पर बधाई दी व प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधक, श्रीमती प्रभा गोयल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति व नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की महत्ता पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मातृभाषा में चिंतन करना सदैव आसान होता है। हिंदी दिवस समारोह में अधिकारी संघ, एनटीयू, ग्राहकगण व वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिनांक 30.09.2020 को हिंदी दिवस समापन समारोह का आयोजन हुआ जिसमें नराकास की सदस्य सचिव, श्रीमती संगीता वशिष्ठ मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में शामिल हुईं। समारोह में हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार विजेताओं व हिंदी माह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुणवत्ता चक्र की प्रस्तुति हिंदी में देने वाली टीमों को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता वशिष्ठ ने राजभाषा कार्यान्वयन के विविध पहलुओं के विषय पर अपने विचार साझा किए। राजभाषा प्रभारी, सुश्री रेखा अग्गरवाल ने यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ सहायक अधिकारी (राजभाषा), श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह ने हिंदी प्रोत्साहन योजनाओं व कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रतिभागियों को आभार व्यक्त किया व आगे भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा प्रकट की।

मन की भाषा प्रेम की भाषा, हिंदी है भारत जन की भाषा।

पीडीआईसी और सीआरएल की राजभाषा गतिविधियां

हिंदी दिवस कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। मुख्य वैज्ञानिक सीआरएल, श्री नन्द कुमार वी और महाप्रबंधक पीडीआईसी श्री मनोज जैन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर माननीय गृहमंत्री, श्री अमित शाह, माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह तथा बीईएल के सीएमडी, श्री एम वी गौतम द्वारा जारी संदेश पढ़े गए।

माह के दौरान "हिंदी निबंध लेखन", "हिंदी नारा लेखन" "हिंदी प्रश्नोत्तरी" प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यह टीम प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता एसएपी के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा 30 सितंबर 2020 को ऑनलाइन माध्यम से की गई।

नवी मुंबई यूनिट में उच्चाधिकारियों हेतु राजभाषा ई–कार्यशाला

नवी मुंबई यूनिट में 24.09.2020 को उप महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर की श्रेणी के उच्चाधिकारियों के लिए राजभाषा ई–कार्यशाला आयोजित की गई। ई–कार्यशाला के अंतर्गत उप महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपरी श्रेणी के 19 अधिकारियों को उनके ई–मेल पर अध्ययन सामग्री (पीपीटी) भेजी गई जिसमें राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, वार्षिक कार्यक्रम 2020–21 के लक्ष्य, राजभाषा प्रावधानों के अनुपालन हेतु यूनिट के संदर्भ में जांच–बिंदु, पारिभाषिक शब्द और उनका वाक्य प्रयोग तथा राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से देश का भाषाई वर्गीकरण ("क","ख" एवं 'ग' क्षेत्र) आदि जैसे विषय शामिल किए गए। इसी दिन इन अधिकारियों के लिए राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें 19 लोगों ने भाग लिया। विजेताओं को हिंदी माह के समापन अवसर पर पुरस्कृत किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता – हिंदी माह समारोह

दिनांक 01 सितंबर, 2020 को हिंदी माह उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीएमडी का संदेश पढ़ा गया। दिनांक 14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। महामारी के वजह से किसी भी अतिथि को इस अवसर पर आमंत्रित नहीं किया जा सका। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री गौतम घोष ने मंगलदीप प्रज्वलित कर हिंदी दिवस का शुभारंभ किया। इसके पश्चात रक्षा मंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा भेजे गए संदेश पढ़े गए। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख ने राजभाषा नीतियों पर जागरूकता के लिए विशेष व्याख्यान दिया। हिंदी माह के दौरान कोविड–19 महामारी से संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 25 सितंबर को हिंदी ई–कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री निर्मल दुबे, उप–निदेशक, राजभाषा कार्यान्वयन, गृह मंत्रालय ने हिंदी माह के महत्व एवं तकनीकी के माध्यम से प्रशिक्षण, निरीक्षण एवं संगोष्ठी के आयोजन पर चर्चा किया गया। दिनांक 28. 09.2020 को राभाकास बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 30.09.2020 को हिंदी माह समापन समारोह का आयोजन कार्यालय प्रधान की अध्यक्षता में श्री गौतम घोष द्वारा किया गया। इसमें हिंदी माह प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ हिंदी माह समारोह का समापन हुआ।

क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में हिंदी माह समारोह

- राजभाषा कार्यालय समिति की बैठक बुलायी गई।
- सितम्बर माह, 2020 में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई।
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख, कमांडर संजीव भेंडे ने हिंदी माह पर रक्षामंत्री,भारत सरकार और सीएमडी,बीईएल के संदेश को पढ़ा। तत्पश्चात सदस्य, श्री नितिन पाटिल ने हिंदी माह के कार्यक्रमों का संचालन किया।
- डा प्रेम जन्मेजय, सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक ने कार्यालय के कार्य हिंदी भाषा के उपयुक्त प्रयोग पर व्याख्यान दिया।
- क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के 6 कर्मचारियों को श्री पचौरी, निदेशक, साफ्टल ने प्रशिक्षित किया।
- विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कोटद्वार यूनिट में हिंदी माह समारोह

कोटद्वार यूनिट में 01 सितंबर से 30 सितंबर, 2020 तक हिंदी माह समारोह मनाया गया। इस दौरान यूनिट के प्रमुख स्थलों पर हिंदी प्रचार–प्रसार संबंधी बैनर लगाए गए। कर्मचारियों के लिए कुल 10 प्रतियोगित्ताएं आयोजित की गई (प्रचार वाक्य, स्वरचित कविता, हिंदी प्रचार–प्रसार से संबंधित पोस्टर, चित्र देखकर अभिव्यक्ति, राजभाषा जागरूकता, निबंध, हिंदी पत्र लेखन, अनुवाद कौशल, वर्ग पहेली, राजभाषा ज्ञान) जिसमें कुल 288 कार्मिकों व शिशिक्षुओं की प्रतिभागिता रही। सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार कोविड–19 के प्रसार को देखते हुए इस वर्ष हिंदी माह के दौरान सभी प्रतियोगिताएं ऑन–लाइन माध्यम से आयोजित की गई।

दिनांक 14.09.2020 को हिंदी दिवस समारोह में यूनिट के महाप्रबंधक सभाकक्ष में प्रभागाध्यक्षों की उपस्थिति में माननीय गृहमंत्री एवं माननीय रक्षा मंत्री एवं सीएमडी द्वारा हिंदी माह दिवस पर प्रेषित संदेशों का वाचन किया गया। साथ ही इस अवसर पर उच्चाधिकारियों हेतु राजभाषा जागरूकता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 'हिंदी माह' समापन समारोह कार्यक्रम में श्री ए रुधिरामूर्ति, महाप्रबंधक द्वारा वर्ष भर हिंदी कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले संचालन प्रभाग को महाप्रबधक चल वैजयंती से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्री मदन कुमार असवाल, सहायक अभियंता को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए तुलसीदास पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही अपने प्रभाग में हिंदी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए श्री जितेन्द्र सिंह, अपर महाप्रबंधक (संचालन) को कबीर पुरस्कार प्रदान किया गया।

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला गाजियाबाद की गतिविधियाँ

हिंदी माह में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए मुख्य वैज्ञानिक, श्री अनूप कुमार रॉय के साथ मुख्य अतिथि नराकास अध्यक्ष श्री महेश सेठ, नराकास सदस्य सचिव श्री ललित भूषण

हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी

हिंदी माह के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता

भारत की आजादी से आत्मनिर्भर भारत बनने तक का सफर

आत्मनिर्भर का शाब्दिक अर्थ होता है "स्वयं पर आश्रित"। अतः स्वाश्रयी और स्वावलम्बी भी इसी के पर्याय माने जाते हैं।

सन् 1700 से पूर्व का भारत – प्राचीन काल से ही भारत का अरब, मिश्र, रोम, फ्रांस, वेनिस, इंग्लैंड एवं जेनेवा के साथ व्यापार होता था। अतः 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि के चरम पर पहुँच चुका था जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। बर्नियर के अनुसार– उस समय का भारत एक ऐसा गहरा कुआँ था, जिसमें चारों ओर से संसार भर का सोना–चाँदी आकर एकत्रित हो जाता था, पर जिसमें से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था।

आर्थिक इतिहासकार अंगस मैडीसन की पुस्तक, द वर्ल्ड इकोनमी–ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव (वैश्विक अर्थव्यवस्था – एक हजार वर्ष का परिप्रेक्ष्य) के अनुसार, भारत विश्व का सबसे धनी देश था और 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यस्था था। विश्व की कुल सम्पति का एक तिहाई से एक चौथाई भाग अकेले मराठा साम्राज्य के पास था। इस समृद्धि का कारण था यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग, जो न केवल प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करते थे बल्कि विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का अग्रणी स्थान सुनिश्चित करते थे।

भारत में उत्पादित वस्तुओं की मांग पूरे विश्व में थी जैसे– आगरा, बनारस तथा गुजरात के रेशमी वस्त्र कश्मीर की ऊनी शॉल एवं लकड़ी की सुन्दर नक्काशीदार चीजें ढाका की मलमल अहमदाबाद का सूती कपड़ा सोने–चाँदी के आभूषण; दिल्ली और मुल्तान की हाथी दाँत की सुन्दर कलात्मक वस्तुएं; बंगाल का पटसन (जूट); धातु का सामान, हथियार आदि।

सन् 1700 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का भारत– औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई। यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी। अतः यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति हेतु एवं तैयार माल की खपत के लिए अफ्रीकी एवं एशियायी देशों में उपनिवेशों की स्थापना की। सभी उपनिवेशों को शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जबरन निर्मित माल की खरीद व कच्चे माल के निर्यात हेतु बाध्य किया गया।

भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास– ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप, भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन–निर्मित आयातित अंग्रेजी माल से भर गया। भारतीय हस्तशिल्प, अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका। दूसरी ओर, भारतीय उत्पादों के लिये यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिये लगभग बंद ही हो गये।

इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे, वहीं नये पाश्चात्य अनुप्रयोगों तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया। भारतीय कारीगर निर्बल और बिखरे हुए थेय अतरू वे मशीन की बनी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे। फलतः उन्हें अपना पुश्तैनी पेशा छोड़कर खेती का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग–धंधों का नाश हो गया तथा लाखों कारीगर भूखे मरने लगे। औद्योगिक क्रांति, जो इंग्लैण्ड के लिए वरदान स्वरूप थी, वही भारतीय उद्योगों के लिए अभिशाप सिद्ध हुई।

भारत एक सम्पूर्ण निर्यातक देश से सम्पूर्ण आयातक देश बन गया। औपनिवेशिक काल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद शेयर 20% से घटकर 5% पर आ गया।

धन–निष्कासन सिद्धान्त दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक "पावर्टी ऐन्ड अनब्रिटिश रूल इन इन्डिया" में सर्वप्रथम आर्थिक निकास या धन–निष्कासन (Drain of Wealth) की अवधारणा प्रस्तुत की। 1905 में उन्होंने कहा था, धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण। धन के निष्कासन के परिणामस्वरूप भारत में पूँजी संचय नहीं हो सका और पूंजी का संचयन नहीं तो औद्योगिक विकास भी नहीं। लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता चला गया और गरीबी बढ़ती चली गई।

स्वदेशी आन्दोलन – यह भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण आन्दोलन, सफल रणनीति व दर्शन था। स्वदेशी का अर्थ है– 'अपने देश का'। इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुँचाना व भारत के लोगों के लिये रोजगार सृजन करना था। यह ब्रितानी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की समग्र आर्थिक व्यवस्था के विकास के लिए अपनाया गया साधन था। आगे चलकर, यही स्वदेशी आन्दोलन महात्मा गांधी के स्वतन्त्रता आन्दोलन का भी केन्द्र बिन्दु बन गया। उन्होंने इसे "स्वराज की आत्मा" कहा है।

आत्मनिर्भर भारत– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की गई जिनका उद्देश्य भारत की अन्य–निर्भरता को समाप्त कर उसे आत्मनिर्भर बनाना था, चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति या फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण।

वर्ष 2020 के प्रारंभ में आई एक वैश्विक महामारी ने लॉक डाउन की स्थितियाँ उत्पन्न की जिससे अनेकों दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार छिन गया और वे पुनः गावों की ओर पलायन हेतु बाध्य हुए। 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है जो देश की सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के द्वारा भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर वस्तुएं अपने देश में ही तैयार करे अर्थात आत्मनिर्भर बने जाए, इसलिए अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। इस अभियान का अर्थ और उद्देश्य विदेशों से भारत में आने वाली वस्तुओं पर अपनी निर्भरता को कम करना है अर्थात हमें ज्यादा से ज्यादा भारत में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना है। उनकी गुणवत्ता में इतना सुधार करना है कि स्वयं भी उनका उपयोग करें और दूसरे देशों में भी बेच सकें।

'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुंबकम' कहकर यह इशारा किया कि भारत पूरे विश्व को अपना घर मानता है। आत्मनिर्भर भारत का अभिप्राय यह नहीं है कि भारत सभी देशों से अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़ देगा। भारत अपनी उन्नति में सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। हम यह चाहते हैं कि दूसरे देश आकर हमारे देश में विनिवेश करें और भारत की बनी हुई वस्तुएं विश्व के हर कोने में पहुंचे ।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ–

1 **अर्थव्यवस्था**– एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो छोटे –छोटे परिवर्तन (इंक्रिमेंटल चेंज) नहीं, बल्कि ऊँची छलांग (क्वांटम जंप) लाए।

2 **बुनियादी ढांचा** – एक ऐसा बुनियादी ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके। भारत की सरकार आधारभूत संरचना में जरूरी निवेश के सुधार करेगी जिससे कि स्वदेशी वस्तुएं बाहर से आने वाले उत्पादों का मुकाबला कर सकें।

3 **प्रौद्योगिकी**– एक ऐसा सिस्टम, जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल हो। आने वाले समय में ऑनलाइन सर्विस को बढ़ावा दिया जायेगा। 21वीं सदी में विकास के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सिस्टम की आवश्यकता है।

4 **जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी)** – भारत की जीवंत जनसांख्यिकी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत हेतु ऊर्जा का स्रोत है। भारत की जनसंख्या में 18 से 35 वर्ष की आयु के लोग सबसे ज्यादा है। इसलिए उन्हें वाइब्रेंट डेमोग्राफी नाम से संबोधित किया गया है। हमारे पास युवा शक्ति का विशाल भंडार है। इस जनसंख्या के भार को मुनाफे में तब्दील करने के लिए हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम देना होगा। उन्हें रोजगार तभी मिल सकता है जब हम लोकल निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें और मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे।

5 **मांग**– भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार और मांग है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। 130 करोड की जनसँख्या वाले भारत देश में वस्तुओं की मांग की कोई कमी नही है। हमे इस भारी मांग का उपयोग अपने देश में निर्मित चीजों की बिक्री बढाने के लिए करना है। इसके लिए हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग– भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई केलिए 50 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा दी गई है।

सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्मव खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए 'वैश्विक पहुंच के साथ वोकल फॉर लोकल' का शुभारम्भ किया गया। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए 'चौंपियंस' पोर्टल लॉन्च किया गया है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए 16 नीतियों की घोषणा की गई। जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं–

- एमएसएमई सहित व्यापार के लिए रुपये 3 लाख करोड़ संपार्श्विक निःशुल्क स्वचालित ऋण।
- एमएसएमई के लिए रु 20 हजार करोड़ का अधीनस्थ ऋण।
- एमएसएमई के फंड के माध्यम से रुपए 50 हजार करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूशन।
- एमएसएमई के लिए वैश्विक टेण्डर की सीमा बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये तक कर दी गई है।
- 3 और महीनों के लिए व्यापार और श्रमिकों के लिए 2500 करोड़ रुपये का ईपीएफ समर्थन।
- एनबीएफसीएस, एचसी, एमएफआई के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की तरलता सुविधा।
- एनबीएफसी के लिए 4500 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना दी गई है।
- डीएस–टीसीएस कटौती के माध्यम से 50 हजार करोड़ रुपये की तरलता प्रदान की गई है।

गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए की गई मुख्य घोषणाएँ–

14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए कुछ मुख्यत घोषणाएं की गई हैं –

- किसानों और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने की पश्च कोविड–19 योजना।
- पिछले दो महीनों के दौरान प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए सहायता योजना।
- दो महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति।
- 2021 तक देश एक राशन कार्ड द्वारा भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना तय हुआ है।

- प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसर बनाने की पहल।
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5 हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा दी जा रही है।
- सीएएमपीए फंड का उपयोग कर 6 हजार करोड़ रोजगार पक्का किया जा रहा है।
- नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजीगत निधि सुनिश्चित की गई है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को बढ़ावा देने के लिए रु 2 लाख रखे गए हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की गई 11 घोषणाएं–

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्यतः ग्यारह प्रकार की घोषणा की गई है।
- अवसंरचना की स्थापना के लिए 11 लाख करोड़ रुपये का कोष
- सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के एक औपचारिककरण के उद्देश्य से एक नई योजना के लायक रु 10 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री मातृ संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये आवंटित
- पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सेटअप किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार जड़ी–बूटियों की खेती के लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
- मधुमक्खी पालन की पहल के लिए 500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
- 500 करोड़ रुपये के सभी फलों और सब्जियों को कवर करने के लिए 'ऑपरेशन ग्रीन' का विस्तार किया जाएगा।
- अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू जैसे आवश्यक भोजन में संशोधन लाया जाएगा।
- विपणन सुधारों को एक नए कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा जो अंतरराज्यीय व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करेगा।
- किसान को सुविधात्मक कृषि उपज के माध्यम से मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन दिया जाएगा।
- चौथा और पाँचवाँ ट्रान्च ज्यादातर संरचनात्मक सुधारों से जुड़ा था, जो कुल मिलाकर 48100 करोड़ का था, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग ₹ 8100 करोड़ है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के लिए 40000 करोड़ रखे गए हैं।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरें, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।

देवराज
प्रबंधक
रेडार एसबीयू, गाजियाबाद

समृद्धि व्यक्ति की देन है, भाग्य की नहीं।
–चाणक्य

स्वरोजगार का सृजन

स्वरोजगार का अर्थ है– स्वयं अपने लिए रोजगार का सृजन करना व उद्योग लगाना जिससे रोजगार के लिए हमें दूसरों पर आश्रित न रहना पड़े और खुद अपना विकास किया जा सके। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारे देश में सरकारी नौकरियाँ कम होती जा रही हैं जिसके कारण बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें स्वयं का उद्योग लगाकर अपने साथ–साथ कई अन्य लोगों के लिए रोजगार सृजित करने की जरुरत है जिससे कि देश की बेरोजगारी खत्म हो सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत अगर हम चाहे तो अपना खुद का उद्योग लगा सकते हैं जैसे कि पापड़ उद्योग, अचार उद्योग, खिलौने उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, रेशम उद्योग ऐसे कई प्रकार के उद्योग हैं जिसमें हम थोड़ी लागत से उद्योग चालू कर सकते हैं और अपने साथ–साथ कई लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी की समस्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना हैं तो हमें अपना खुद का उद्योग लगाने जैसे निर्णय लेने होंगे और रोजगार करना होगा।

देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं के रोजगार से अपने जीवन को बड़े पैमाने पर ले जाकर विकास का परचम लहराया है और ऐसे लोग आज तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुँच गए हैं। स्वयं का रोजगार छोटा या बड़ा नहीं होता बस उसे करने का हुनर हमारे पास होना चाहिए और उसको पूरी मेहनत और पूरी योजना के साथ करना चाहिए। जब हम खुद का उद्योग शुरु करते है तो हमारे बाद हमारे बच्चों को भी उद्योग या व्यापार के माध्यम से रोजगार मिलता है। अगर हमें अपना और अपने परिवार का विकास करना है तो स्वयं का रोजगार करने की आवश्यकता है। इनसे ही हमारे सपने और आशाएं पूरी हो सकती हैं। हमारे देश में कई योजनाएँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है जिसमें सरकार ऋण देकर सहायता करती हैं। ऋण की सुविधा का लाभ लेकर हम अपना स्वयं का कोई रोजगार कर सकते हैं। हम सरकारी ऋण लेकर अपने व्यवसाय को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। कई लोग इस योजना के माध्यम से लाभ ले भी रहे हैं।

गांवों में कई लोग इस योजना के माध्यम से मत्स्य पालन, मुर्गी पालन कर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। जिंदगी में अगर सफल होना हो तो हमें पूरी योजना के साथ स्वयं का कुछ काम करना आवश्यक हैं जब तक हम स्वयं का कोई काम नहीं करेंगे, हम दूसरों के भरोसे बने रहेंगे। कुछ लोग स्वयं का कार्य करने के लिए चाय का ठेला लगाकर 200 से 300 रूपये प्रतिदिन कमाकर अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं तो कुछ लोग समोसा, कचोरी, पकौड़ी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं और कुछ लोग बाजार में कई तरह की दुकानें भी खोल कर अपना कार्य शुरू करते हैं। यह लोग दूसरों के ऊपर निर्भर न रहकर अपना स्वयं का रोजगार कर रोजी-रोटी कमाकर अपने और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करते हैं।

स्वरोजगार के लिए हमारे देश में सरकार की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाता हैं, जिससे हम रोजगार करने के तरीके सीख सकते हैं और अपना रोजगार लगा सकते हैं। जो व्यक्ति स्वरोजगार की ट्रेनिंग लेकर व्यवसाय करता है वह अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करता हैं और उस व्यक्ति को दूसरों के सहारे की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वह स्वयं का रोजगार करता हैं। सरकार के माध्यम से ट्रेनिंग देकर बैंक के माध्यम से लोन दिलाकर युवाओं की मदद की जाती हैं जिससे वह आगे बढ़ सके। कहा जाए तो स्वरोजगार एक प्रकार से आत्मनिर्भरता है जो किसी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर न रहकर खुद की बुनियाद को मजबूत बनाता है। मोदी जी के इस अभियान को सम्पूर्ण भारत की जनता अपनाकर अपना और अपने परिवार के भविष्य की बुनियाद खुद बना सकता है।

के. धनबाल

सहायक अभियंता, उत्पाद आश्वासन, चेन्नै

"एमएसएमई"

एमएसएमई से अभिप्राय है सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रकार के उद्यम। भारत सरकार ने सन् 2006 के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई है। यह उद्यम मुख्यतः उत्पादन, विनिर्माण, उत्पाद प्रसंस्करण या संरक्षण में कार्यरत है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) या देशी उत्पाद के लगभग 6%विनिर्माण का लगभग 45% और निर्यात का लगभग 40% योगदान एमएसएमई के द्वारा दिया जाता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

मिशन– नागरिकों को सशक्त बनाना, ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस उद्योगों के समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देना, इंटरनेट गवर्नेंस में भारत की भूमिका को बढ़ाना तथा एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना, दक्षता बढ़ाना और डिजिटल सेवाओं के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

उद्देश्य–

ई–सरकार– ई–सेवाओं की डिलीवरी के लिए ई–आधारभूत संरचना प्रदान करना।

ई–उद्योग– इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण और आईटी–आईटीईएस उद्योग को बढ़ावा देना।

ई–इनोवेशन/ आर एंड डी– आर एंड डी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन – आर एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सक्षम बनाना। अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए आईसीटी और ई के क्षेत्र / तंत्र की स्थापना।

ई–लर्निंग– ई कौशल और ज्ञान नेटवर्क के विकास के लिए सहायता प्रदान करना।

ई–सुरक्षा– भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित करना।

ई–समावेश– अधिक समावेशी विकास के लिए आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा देना।

इंटरनेट गवर्नेंस– इंटरनेट गवर्नेंस के ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भारत की भूमिका बढ़ाना।

एमएसएमई ने न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं बल्कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान दिया है। 2018–19 की वार्षिक गणना के अनुसार भारत में लगभग 6,08,41,245 एमएसएमई हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है–

उद्यम का प्रकार	विनिर्माण उद्यम संयंत्र और मशीनरी निवेश	उद्यम का प्रकार उपकरणों में निवेश	सेवा प्रदाता उद्यम
सूक्ष्म	<= 25L	सूक्ष्म	<= 10 L
लघु	>= 25L —— <= 5 Cr-	लघु	>= 25 L —— <= 5 Cr-
मध्यम	>= 5Cr —— <= 10 Cr-	मध्यम	>= 5 Cr —— <= 10 Cr-

पूर्व में यह वर्गीकरण ऊपर दी गई तालिका में दर्शाए गए "निवेश" की बुनियाद पर किया जाता था। परंतु 2018 में प्रस्तुत किए गए विधेयक के द्वारा इसे फिर से परिभाषित किया गया और एमएसएमईस को वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा गया। नई तालिका कुछ इस प्रकार से है–

उद्यम का प्रकार	निवेश	वार्षिक कारोबार
सूक्ष्म	1 Cr	5 Cr
लघु	10 Cr	50 Cr
मध्यम	50 Cr	250 Cr

सफल एमएसएमई को हमेशा यह डर रहता था कि यदि वे एमएसएमई की परिभाषित सीमा को बढ़ाएंगे तो अपने हक के लाभ को खो देंगे, इस वजह से वे बढ़ने के बजाए परिभाषित दायरे में रहना पसंद करते थे। परंतु नए परिवर्तनों के अनुसार अब दायरा बढ़ा दिया गया है। इससे बहुत फायदा हुआ है। अब संयंत्र और मशीनरी पर निवेश की बार–बार निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एमएसएमई का संचालन भी पारदर्शी हो गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान सन 2020 की एमएसएमई की नई योजना, जिससे लगभग 45 लाख इकाईयों को लाभ होगा, के तहत दी गई कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं –

- एमएसएमई को कॉलेटरल फ्री लोन का प्रावधान;
- एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ की व्यवस्था;
- एमएसएमई के लिए 12 महीनों की एक अधिस्थगन अवधि ;
- विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने वाले एमएसएमई को समान संस्थाएं मानना;
- शतप्रतिशत क्रेडिट गारंटी – एमएसएमई ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े उद्योगों की तुलना में कम लागत वाले क्षेत्रों के औद्योगिकरण में मदद की है, साथ ही में देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है–

★ एमएसएमई श्रमिकों और कारीगरों के कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें रोजगार देकर ऋण तथा अन्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
★ बैंकों को धन सहायता प्रदान करते हैं और उद्यम विकास के साथ ही विशेष प्रशिक्षण केंद्र शुरू करके कौशल को बढ़ावा देते हैं।
★ एमएसएमई बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं।
★ घरेलू तथा निर्यात बाजारों तक पहुंच कर उचित सहायता प्रदान करने के साथ–साथ आधुनिक परीक्षण सुविधाएं तथा गुणता प्रमाणन सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
★ एमएसएमई अब उत्पाद विकास, डिजाइन नवाचार, पैकेजिंग का समर्थन भी करते हैं।
★ एमएसएमई ने खादी और जूट उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में बहुत मदद की है।

यह एमएसएमई कम निवेश, परिचालन में लचीलापन, स्थानों के माध्यम से गतिशीलता, आयात की कम दर, घरेलू उत्पादन में अधिकतम योगदान : जैसे विविध क्षेत्रों में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार एमएसएमई ने लगभग 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है और कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र माना जाता है।

वर्ष 2016–17 की रिपोर्ट के अनुसार जी.वी.ए. (ग्रोस वैल्यू एडेड) में एमएसएमई का योगदान लगभग 31.83% रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपना योगदान 50% करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देकर वैश्विक आर्थिक घाटा और प्रतिकूलताओं से बचाव करता है और यह एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कार्य प्रसंशनीय है।

दुनिया में एमएसएमई को आर्थिक विकास और एक समान विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वीकार किया गया है। अर्थव्यवस्था में विकास की उच्चतम दर उत्पन्न करने में कम निवेश, लचीला संचालन और उचित देशी औद्योगिकी विकसित करने की क्षमता के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के कार्य में एमएसएमई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अत: भारत के परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई एक वरदान साबित होगा।

दीपाली सुहास राव
सहायक अभियंता, गुणता प्रबंधन – पुणे

ऐसा मेरा देश महान

कहीं राम का डंका बाजे, कहीं रहीम का गूंजे नाम,
ऐसा मेरा देश महान।

माटी सोना, अमृत पानी, पत्ता–पत्ता गुणों की खान,
ऐसा मेरा देश महान।

कोस –कोस पर बदले बोली, फिर भी एक है हिन्दुस्तान,
ऐसा मेरा देश महान।

हर क्षेत्र में लोहा मनवाया, चाहे कला हो या विज्ञान,
ऐसा मेरा देश महान।

योग का सबको पाठ पढ़ाकर, विश्व–स्तर से दिलवाया सम्मान,
ऐसा मेरा देश महान।

कोविड में दर्शाए सेवा भाव को, विश्व–भर ने किया प्रणाम,
ऐसा मेरा देश महान।

दुश्मन को भी गले लगाया, बनकर आया जब मेहमान,
ऐसा मेरा देश महान।

अंतरिक्ष में भी नाम कमाया, मंगल हो या चंद्र–यान,
ऐसा मेरा देश महान।

माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल, भारतीय है हर जगह की शान,
ऐसा मेरा देश महान।

दुश्मन को भी खूब छकाया, चीन हो या हो पाकिस्तान,
ऐसा मेरा देश महान।

जात –पात से ऊपर उठकर,
आओ बनाये एक नया जहांन
अमन–चैन के फूल खिले हो,
गुलिस्तां बन महके हिन्दुस्तान।

सोने की चिड़िया पंख पसारो,
भरनी है एक ऊँची उड़ान,
छूनी है कुछ नयी बुलंदियां,
राह देख रहा यह आसमान।

ऐसा मेरा देश महान
जय जय जय जय हिन्दुस्तान।

शिवानी कपूर,
स्टाफ सं. 214045
केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गाजियाबाद

बच्चों के लिए उपयोगी ऐप्स

यू–ट्यूब किड्स (You tube kids)	ये ऐप बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ऐप पर बच्चे वीडियो, चैनल और प्ले लिस्ट को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं।
नेक्स जीटीवी किड्स (nex GTV kids)	इस ऐप की मदद से बच्चे टेल्स ऑफ पंचतंत्र से लेकर डकटेल्स व मालगुडी डेज जैसी दिलचस्प कहानियों से मनोरंजन कर सकते हैं।
निक ऐप (Nick App)	बच्चे मजेदार वीडियो, गेम्स, निकेलेडियन के हाल–फिलहाल के कुल एपिसोड का आनंद उठा सकते हैं।
ऐपी स्टोर (Appy Store)	यह आठ साल के बच्चों के लिए है। बहुत कुछ नई चीजें सीख सकते हैं।
लाइव किड्स (LIV kids)	सोनी नेटवर्क्स इंडिया द्वारा पेश इस ऐप में नर्सरी राइम्स मिल जाएंगी।

आत्मनिर्भरता - राष्ट्रीय अभिप्राय

लोकतंत्र का अर्थ है– अपनों के द्वारा अपनों के लिए अपना शासन। वैसे ही आत्मनिर्भर भारत का मतलब है– अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करना, फिर चाहे वह उत्पाद हो या सेवा।

आत्मनिर्भरता का इतिहास – आत्मनिर्भर भारत, भारत सरकार द्वारा की गई ऐसी पहल है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया है। अगर इस शब्द आत्मनिर्भर की बात करें तो ये कोई नया नारा नहीं है। आजादी के समय गांधीजी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था जिसका उदेश्य था कि भारतवासी अपने देश में बनी वस्तुओं को ज्यादा महत्व देंगे या उनका ही प्रयोग करेंगे। खादी आंदोलन की बात करें या दांडी यात्रा की, गांधीजी ने सभी में एक ही नारा दिया गया था– स्वदेशी। परंतु समय के साथ–साथ ये नारा कहीं खो सा गया था। पिछले कई दशकों से हम विदेश में बने उत्पादों व वहाँ की सेवाओं के गुलाम रहे हैं या यूं कहें कि गुलाम बने हुए हैं। अंग्रेजों ने भले ही भारत को 74 साल पहले छोड़ दिया हो परंतु मानसिक रूप से वो हमें गुलाम बना कर ही गए थे। हम अपने दैनिक जीवन में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग निरंतर रूप से और बेझिझक करते आ रहे हैं और ऐसा कर अपने गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ओर जहां हम अपनी धनराशि को विदेशी उत्पादों पर खर्च करते रहे हैं वहीं दूसरी ओर हम विदेशी ताकतों को ओर मजबूत व खुद को निरंतर कमजोर बनाते आ रहे हैं।

वर्तमान भारत – आज के अंतराष्ट्रीय युग में व्यापार का विस्तार कई गुना बढ़ा है। आज एक देश में बनी वस्तु का उपभोग दूसरे देशों में बड़ी आसानी से किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत का सकल आयात $598.62 बिलियन तथा सकल निर्यात $528.45 बिलियन है। भारत विश्व का दूसरे नंबर का देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है। ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिनके लिए भारत विदेशों पर निर्भर है।

हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि किसी देश या भारत को विदेशी वस्तुओं का प्रयोग बिलकुल नहीं करना चाहिए। हमारा आशय यह है कि कोई भी देश आर्थिक व सामाजिक रूप से तभी मजबूत हो सकता है जब अपने देश में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर उसकी निर्भरता ज्यादा हो। विदेशों पर हमारी निर्भरता उन देशों की अर्थ व्यवस्था को निरंतर बढ़ा रही है। आज बहुत से देशों ने विदेशी व्यापार में अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। आज हर दूसरी चीज जिसका हम प्रयोग करते हैं या तो चीन में बनी होती हैं या उस वस्तु के उपकरण चीन में बने होते हैं। चीन पहले तो अपने उत्पादों को सस्ता देकर लोगों को उनका आदी बना देता है और जब लोग वहाँ की चीजों के आदी बन जाते हैं तो उनसे मनमाने पैसे वसूलता है या उनकी गुणवत्ता में कमी कर देता है जिससे वो उत्पाद लंबे समय के लिए नहीं चल पाएं। ऐसे समय में ये निर्णय लेना जरूरी हो गया था कि लोग स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करें। इसलिए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की न केवल पहल की है बल्कि इस दिशा में ठोस कदम भी उठाए हैं।

आत्मनिर्भर भारत का रक्षा क्षेत्र में योगदान – रक्षा क्षेत्र सदैव से ही किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अपने ज्यादातर उपकरण दूसरे देशों से आयात करता है। यदि इस क्षेत्र के उपकरण और प्रणालियों की डिजाइन, विकास और उत्पादन हमारा हो तो न केवल ये उपकरण सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे बल्कि इन उपकरणों और प्रणालियों को हम उच्चतम गुणवत्ता के साथ खरीद सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे– एक तो हम जरूरत पड़ने पर रक्षा उपकरणों को सरलता से प्राप्त कर सकेंगे और दूसरा इन उपकरणों की बिक्री से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

इसी पहल को आगे बढ़ते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त 2020 को 108 रक्षा उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाते हुए इन उपकरणों का अपने देश में ही उत्पादन करने का निर्देश दिया है। इन उपकरणों का आयात हम निरंतर रूप से करते आ रहे हैं । अब इन जैसे अनेक उपकरणों को भारत में ही बनाया जाएगा जिससे भारत के घरेलू

उद्योगों में कमाई के अवसर पैदा होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। घरेलू उद्योगों को आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ के आदेश प्राप्त होंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

भारत सरकार निरंतर निजी घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा उसका निर्यात करने पर जोर दे रही है। भारत 2014 से 2018 तक विश्व का दूसरे नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा रक्षा उपकरणों का आयात करता है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए 2025 तक 1.7 ट्रिलियन सकल बिक्री का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रक्षा बजट को वित वर्ष 2020–21 में 9.37% यानि 471378 करोड़ रु. तक बढाया गया है। सरकार निरंतर मेक इन इंडिया अभियान पर बल दे रही है। रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया अभियान को भली–भांति लागू किया जा रहा है।

भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जिसके बाद भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप को लांच किया गया है। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चौलेंज दो ट्रैक में काम करेगा। ट्रैक–1 मिशन मोड में काम करते हुए अच्छी गुणवत्ता के ऐप्स की पहचान करेगा। ट्रैक–2 के तहत नए ऐप्स और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए डिजाइन से लेकर उत्पादन और उसके बाद बाजार की पहुंच तक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस ऐप के माध्यम से मौजूदा ऐप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, ई–लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज और सोशल नेटवर्किंग की श्रेणियों वाले ऐप्स को सरकार अपना मार्गदर्शन देने के साथ समर्थन देगी।

प्रधानमंत्री जी का संदेश भाषण – डिफेक्सपो –2020 के अपने उद्घाटन भाषण में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 वर्षों के लिए दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) के गठन की घोषणा की थी। संख्या, विनिर्देशों और समय–सीमा सहित सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के बारे में उद्योग को अग्रिम रूप से सूचित करना आवश्यक है। यह वर्तमान में एलटीआईपीपी के एक अप्रकाशित संस्करण के माध्यम से किया गया है जिसे प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर) कहा जाता है। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों की कुछ आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए नवीनतम टीपीसीआर 2018 का गठन भी किया है। उद्योग सुरक्षित रूप से निवेश करने में सक्षम हो सकें, इसलिए, टीपीसीआर को "रक्षा औद्योगिक योजना दस्तावेज" से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिसका उदेश्य यह होना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं को दी गई समय–सीमा के भीतर खरीदा जायेगा। इसके अलावा, स्पष्ट व्यापार योजना व नीति एफडीआई को भी आकर्षित करने में मदद करेगी।

चुनौतियाँ– हमारी कुछ रक्षा यूनिटें/उद्योग–धंधे अपने रक्षा उपकरणों को भारत के बजाय विदेशों में बेचना ज्यादा पसंद करते है क्योंकि भारत में उनको अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मूल्य संबंधी इस समस्या के लिए भारत सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू उद्योगों को अपना उपकरण भारत में बेचने से किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न हो अन्यथा आत्मनिर्भर का हमारा यह उदेश्य सफल नहीं हो पाएगा।

निष्कर्ष– अब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा मे अग्रसर हो चुका है। इसके परिणाम दूरगामी होंगे और भविष्य में इसके अनेक फायदे देशवाशियों और देश को प्राप्त होंगे। इसको सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग देना होगा ओर देश के साथ कंधे से कंधा मिलकर चलना होगा।

आत्मनिर्भरता आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है, इसलिए, आइए हम मिलकर देश के विकास में योगदान दें और वैश्विक आपूर्ति कड़ी में अपनी भूमिका निभाएं। आज भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कोविड–19 महामारी की आपदा के रूप में खड़ी है। ऐसी परिस्थिति में भारत की संस्कृति और संस्कार हमें संसार के सुख, सहयोग और शांति का संदेश देते हैं। आइए, हम सब मिलकर अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ इस महामारी का सामना करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर करने के लिए अपना योगदान दें।

हनी शर्मा, लेखा अधिकारी
बी ई एल, कॉर्पोरेट कार्यालय

प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली

जीवन गति का नाम है, प्रगति का नाम है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डाला है। हमारे वैयक्तिक और व्यावसायिक जीवन पर प्रौद्योगिकी पूर्णत: आच्छादित है।

प्रारम्भ में मनुष्य द्वारा किए गए दुष्कर कार्यों को मशीन द्वारा सरलता और निपुणता से कर पाना ही तकनीकी प्रगति कहलाता था। वह मैकेनिकल अथवा यान्त्रिकी युग था। धीरे–धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रादुर्भाव हुआ और टीवी, रेडियो और संचार जैसे उपकरण अस्तित्व में आए। यांत्रिक मशीनों के नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। भारी लीवरों का स्थान छोटे स्विचों ने ले लिया। ऊर्जा खपत कम हो गयी, इलेक्ट्रॉनिक्स ने और प्रगति की। सिस्टम एनालॉग से डिजिटल हो गए। मशीनें और भी छोटी हो गई। नियंत्रण और प्रबल हो गये। विज्ञान की नयी शाखाओं ने जन्म लिया– कंप्यूटर साइंस, इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी, नैनो तकनीक आदि। नए–नए उपकरण बनते गए और हमारे जीने का तरीका बदल गया। मानव पहले तो इसका उपयोग मात्र मशीनों में कर रहा था परंतु अब इसका उपयोग औद्योगिक स्तर पर और प्रशासनिक कार्य–विधियों में भी किया जाने लगा।

औद्योगिक स्तर पर प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली –

उद्योग–धंधे देश की अर्थ व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं और आज की अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी चलित है, ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी चलित संगठनों के सफल होने की संभावनाएं अधिक है।

वर्तमान समय में हर संगठन द्वारा कुछ हद तक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परंतु एक प्रौद्योगिकी चलित संगठन वह होता है जिसका कारोबारी मॉडल, नवाचार की रणनीति और विकास, प्रौद्योगिकी केन्द्रित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वे डिजिटल संस्कृति, कार्यस्थल और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसार कार्य करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तकनीक हैं– कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स आदि।

प्राय: परिवर्तन क्रमिक और वृद्धिशील होता है किन्तु आज, तकनीक परिवर्तन की रफ्तार और उसके प्रभाव अभूतपूर्व है। इसका एक मूल कारण है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और उसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास। मशीनों को प्रोग्राम करने के बजाय अब प्रशिक्षित किया जाता है। हार्ड कोड अनुदेशों का स्थान मानव बुद्धि जैसी इस कृत्रिम बुद्धि ने ले लिया है। आज इंटेलिजेंट अलगोरिथम, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी को क्षणों में खोज लेती है, स्वचालित खेती से पैदावार बढ़ाई जा रही है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भीड़ जमाव से बचाता है और वर्चुअल असिस्टेंट, ग्राहकों की समस्याओं को दूर करता है। ए. आई. बहुत जल्द वाणिज्य, उद्योग और सरकारी सभी क्षेत्रों में नए–नए अनुप्रयोगों के रूप में आगे आया है। अब लोगों को कार्य संस्कृति के इस नए मॉडल में वैसे ही ढलना होगा जैसे वे डिजिटल संस्कृति में बदले थे।

इस तकनीकी बदलाव का प्रभाव केवल तकनीक आधारित कंपनियों पर ही नहीं पड़ा बल्कि छोटी–बड़ी सभी कंपनियों पर पड़ा है। प्लेटफार्म एकोसिस्टम में अमेजन का इ कॉमर्स सूट और फिलिप्स का हॉस्पिटल टू होम प्लेटफॉर्म इसका एक बड़ा उदाहरण है। ऐसे प्लेटफॉर्म सभी प्रतिस्पर्धियों और दूसरे उद्योगों पर भी प्रभाव डालते हैं।

प्रौद्योगिकी ने विभिन्न स्तरों और विभागों में कौशल की आवश्यकताओं को भी बदल दिया है। प्राथमिक डिजिटल कौशल अब भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु तकनीकी कौशल तो सिर्फ एक शुरुआत है, आवश्यकता है कुशल,

व्यापारिक बुद्धि वाले ऐसे लोगों की जो प्रौद्योगिकी को तुरंत अपना करते हैं और इस परिवर्तन को मूर्त रूप दे सकते हैं। ऐसे लोग जिनमें नई आवश्यकताओं को जल्द समझने, शीघ्रता से अमल में लाने की क्षमता हो।

कंपनियों को प्रौद्योगिकी के अनिवार्य प्रभावों को समझना होगा। कहाँ इन सिस्टमों द्वारा पैसे की बचत की जा सकती है? किस तरह का कारोबारी मॉडल बनाना होगा? किस तरह का कार्यबल विकसित करना होगा? कार्यबल को किस तरह की संभावनाएं और अवसर दिए जा सकते हैं? आदि। यह सब कुछ समझ कर ही वे संगठन दूसरों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली एक व्यक्ति के रोजगार से लेकर एक संगठन को ऊंचाइयों तक ले जाने के हर पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है।

प्रशासनिक स्तर पर प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली –

न केवल फैक्टरियों में परिवर्तन आया बल्कि कार्यालयों का भी आधुनिकीकरण हो गया। भारी–भारी फाइलों का स्थान अब कंप्यूटर के स्टोर जैसे एक छोटे से फोल्डर ने ले लिया है। सूचनाएँ चुटकी बजाते ही उपलब्ध होने लगी हैं। अब सरकारी दफ्तरों में बाबू फाइलें लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग दौड़ते–भागते नजर नहीं आते हैं। सारी सूचनाएँ अब सॉफ्ट फाइलों के रूप में डाटा बेस में सेव की जाती हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी प्रणाली पिछली सदी की तकनीक की नहीं अपितु प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि विभागों के डाटा बेस बनाए जाएं। इन्हें नेटवर्क द्वारा विभिन्न शहरों और कार्यालयों में लिंक किया जा रहा है जिससे कि ऑनलाइन अपडेशन होता रहे यानी सारे कार्यालयों में सूचनाएँ एक साथ अद्यतन होती रहे। इसका एक टर्मिनल सामान्य जनता के लिए भी खोला जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जन सामान्य को अपने मामले की वर्तमान स्थिति का पता चलता रहे।

हाल ही में उड़ीसा सरकार ने 8 ऐसी योजनाएँ लागू की हैं जिनमें स्पेस तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर भुवनेश्वर में कीमती सरकारी जमीनों की सुरक्षा की जा सके और इसका योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सके। इसे BLUIS – भुवनेश्वर भूमि उपयोग आसूचना प्रणाली नाम दिया गया है। इनके अलावा E&Pravesh विजिटर पास प्रबंधन प्रणाली, E–Bhawan - ओड़ीशा भवन प्रबंधन प्रणाली, E&A जपजीप– राज्य अतिथि गृह प्रबंधन प्रणाली, HRMS 2-0– मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, HRMS मोबाइल ऐप LMS 2.0– मुकदमा प्रबंधन प्रणाली और ORTPSA– अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी और सुपुर्दगी हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल डैशबोर्ड जैसी प्रौद्योगिकी चलित प्रणालियों द्वारा गृह, सामान्य प्रशासन और लोक–शिकायत के उपाय उपलब्ध कराए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा भी ई–खरीद हेतु GeM पोर्टल यानी सरकारी ई–मार्केट बनाया गया है जिससे सभी छोटी– बड़ी कार्यालयीन खरीद आसानी और पारदर्शिता से की जा सके। यहाँ सभी क्रेता और विक्रेता एक ही पोर्टल पर उपलब्धल होते हैं और टेंडर निकालने, बोली लगाने और टेंडर मिलने तक का सारा कार्य वेबसाइट पर ही होता है। इसके बाद विक्रेता आवश्यक सामग्री की आपूर्ति संबंधित विभाग को करता है। बीईएल भी पूँजीगत मदों की खरीद के लिए सफलतापूर्वक GeM पोर्टल का उपयोग कर रही है। सरकार ने अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को भी इसका उपयोग करने का निर्देश दिया है। प्रौद्योगिकी चलित प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई देरी या कोई पक्षपात नहीं होता अपितु सारे तथ्य पारदर्शी होते हैं। शुरुआत में थोड़ा असहज लगता है लेकिन कुछ समय उपयोग करने पर सब सरल हो जाता है।

"आवश्यकता आविष्कार की जननी है"। आविष्कार होते गए और हम इनके साथ आगे बढ़ते गए। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग सृजन के लिए करते हैं या विनाश के लिए। आवश्यकता है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और इसे ऐसे प्रयोग में लाए कि प्रौद्योगिकी चलित प्रणालियों का सर्वोत्तम उपयोग हो सके।

कविता पटेल
तकनीकी साहित्य, बेंगलूरु कॉम्पलेक्स

गुणवत्ता से मजबूत होगा लोकल

वोकल फॉर लोकल महज एक नारा नहीं है। यह देश के उद्योग–धंधों को आगे बढ़ाने, रोजगार छूटने की आशंकाओं से सहमे लोगों और अर्थव्यवस्था को संभालने का ऐसा मंत्र है, जिसकी सार्थकता पर संदेह नहीं किया सकता। स्वदेशी को प्रोत्साहन देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति में बापू के महान विचारों की महक भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान करके देश को कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर आए संकट से उबारने की जो राह दिखाई है, उस पर चलना उतना आसान नजर नहीं आता। कुछ उद्योगपतियों की बेईमानी इस सुनहरे सपने को पूरा करने में बड़ी बाधा बनकर सामने आने लगी है।

कई कारणों से स्थानीय उद्योगों को आगे बढ़ाने की राह कभी आसान नहीं रही। पहला तो यह कि विदेशी उत्पादों के प्रति लोगों में एक अलग किस्म का आकर्षण रहा है। इसके अलावा बाजार की सोच भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा नहीं देती। उपभोक्ता पहले से ही ब्रांडेड उत्पाद लेना पसंद करते हैं। अक्सर व्यापारी भी उत्पादों की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए उत्पाद महंगे होने की उपभोक्ता की आपत्ति को यह कहकर खारिज कर देते हैं कि यह कम कीमत में मिलने वाला लोकल उत्पाद नहीं है। वर्षों से यही होता आ रहा है। स्थानीय उत्पाद भले ही बेहतर क्यों न हों, उपभोक्ता और बाजार उन्हें आसानी से मान्यता नहीं देते हैं।

प्रधानमंत्री ने कोरोना से उद्योग–धंधों, बाजार और अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे को देखकर स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है, लेकिन उन्होंने घटिया उत्पादों की पैरोकारी कतई नहीं की है। स्थानीय उत्पाद बाजार में तभी पैर जमा सकते हैं, जब उनकी गुणवत्ता संदिग्ध न हो। उनका उपयोग करने के बाद उपभोक्ता पर उनकी छाप पड़नी ही चाहिए। किसी भी उत्पाद की छाप उसके प्रति मुखर लोगों की संख्या से नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता से ही पड़ सकती है।

उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है, तो उपभोक्ता कुछ अधिक कीमत चुकाकर भी उसे खरीदना पसंद करेगा। लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में स्थित आधा दर्जन कंपनियों के सैनिटाइजर के सैंपल फेल होना महज इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि इन छह कारखानों ने घटिया सामग्री का उत्पादन करने का अपराध किया है, बल्कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि इसने वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य पर चोट की है।

कोरोना से बचाव के लिए बाजारों में सैनिटाइजर की मांग बहुत बढ़ गई है, ऐसे दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप उत्पादन कर उसे अपेक्षाकृत कम कीमत और ज्यादा गुणवत्ता के साथ बाजार में उतार कर भी मुनाफा कमाया जा सकता है। तमाम उत्पादक ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी का सहारा लेने वालों ने सैनिटाइजर में मानकों के अनुरूप एल्कोहल न मिलाकर स्थानीय उत्पादों की साख बनाने की कोशिशों को धक्का पहुंचाया है। पिछले दिनों ऐसे छह कारखानों के सैनिटाइजर के सैंपल जांच में फेल हो जाने से इस गंभीर मामले का खुलासा हुआ।

प्रधानमंत्री के स्वदेशी पर जोर देने के बाद देश की प्रमुख कंपनियों ने अपनी रणनीति और अभियानों में स्वदेशी को महत्व देना शुरू कर दिया है। अनेक कंपनियां यही कर रही हैं। लेकिन बाजार में अपनी जगह न बना पाने वाली कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री का आह्वान जहां नई राहें खोलने वाला है, वहीं कुछ कंपनियों की बेईमानी उनकी राह को और कठिन बना सकती है।

स्थानीय उत्पादों को महत्व देने के आह्वान के रूप में आत्मनिर्भरता का यह मंत्र उद्योग–धंधों और अर्थव्यवस्था के साथ

ही पूरे देश को कोरोना से उपजे अंधकार और अनिश्चय की स्थिति से उबार सकता है। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय उत्पादों को स्थानीयता की महक से संवारा जाए और बेईमानी पर निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं में स्थानीय उत्पादों के प्रति भरोसा पैदा हो।

मोहित जैन, प्रबंधक
पीडीआईसी (क्रिप्टो समाधान),
बेंगलूरु यूनिट

अब आ गया है समय

लूट रहे विदेशी हमको सस्ते घटिया सामानों से,
बेरोजगारी से जूझ रहे हम, अपनों के अपनानों से।
आ गया है अब समय कि लें इस जिल्लत को अपने अभिमान पर,
शुरू करें बनाना एक नया भारत आत्मनिर्भरता अभियान की बुनियाद पर।।

शुरूआत कर स्वदेशी की, किया बापू ने अंग्रेजों पर घात।
चले गए अंग्रेज पर,
लगा ली हमने बाहरी सामानों की राग।
अब आ गया है समय की छोड़ें दूसरों पर खुद की छाप,
शुरू करें पूरी दुनिया में पहुंचाना अपने कार्यों से अपनी बात।।

अभियांत्रिकी हो या प्रौद्योगिकी, उत्पादन हो या विज्ञान,
होती है हमारी गिनती सबसे ऊपर, हर तरफ है छाया हिन्दुस्तान।
अब आ गया है समय कि लोकल फॉर वोकल का अपनाये ज्ञान,
शुरू करें प्रयोग उन वस्तुओं का जो बढ़ाएं हमारे देश की शान।।

अब "वोकल फॉर लोकल" और "लोकल फॉर वोकल" मंत्रों को है बढ़ाना,
अपनी शक्ति और कौशल से है दुनिया पर छा जाना।
अब आ गया है समय करने का खुद के काबू में अर्थ व्यवस्था का ये खजाना,
आज मिलकर हमें एक समृद्ध आत्मनिर्भर भारत है बनाना।।

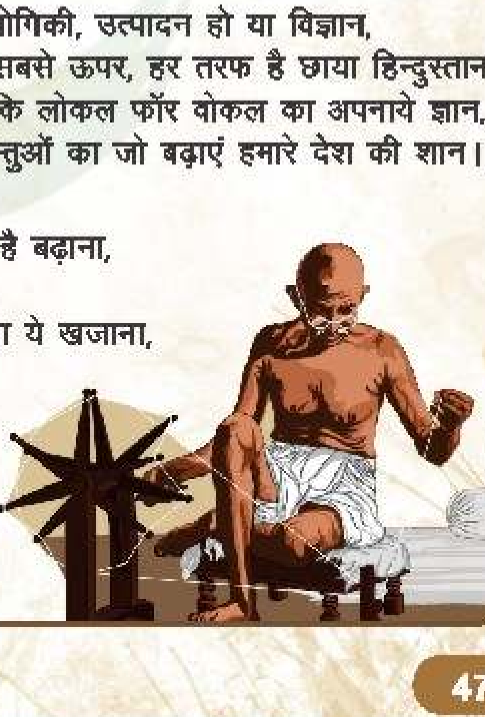

शिवानी सिंह
एमआरएस
सीआरएल, गाजियाबाद

रक्षा क्षेत्र में स्वायत्त भारत

आधुनिक जगत में कोई राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, ये उसकी राजनीतिक, आर्थिक स्थिति तथा रक्षा प्रणाली की आधुनिकता एवं उसके आकार पर निर्भर करता है। भारत हमेशा से पहले आक्रमण न करने के नियम तथा रक्षात्मक शैली पर चला है। भारतीय प्रायद्वीप की वैश्विक राजनीति ही इस प्रकार की है कि बिना शक्ति विस्तार के यहां भारत के अस्तित्व को बनाए रखना आसान नहीं है। आज प्रथम विश्व के देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी पर पकड़ कई देशों से अधिक है। ऐसे राष्ट्र अपने आर्थिक फायदों को देखते हुए उन्नत रक्षा प्रणालियों की बिक्री अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी करते हैं। ऐसे में भारत के लिए धुरविरोधियों के बीच में रहते हुए उन्नत रक्षा प्रणालियों व प्रौद्योगिकी में अपना वर्चस्व बनाए रखना और भी आवश्यक हो जाता है। हमारी निर्भरता हमारे कई मित्र राष्ट्रों पर बनी हुई है। 21वीं सदी में ये निर्भरता समाप्त तो नहीं हुई है पर पिछली सदी की तुलना में हम विश्वसनीय रूप से आत्मनिर्भर हुए हैं। रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रगति पर विचार करते हुए इसका आकलन किया जा सकता है।

वायु रक्षा प्रौद्योगिकी– भारत की वायु सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। वायु सेना ने भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित मारुत जहाज को अपने बेड़े में 1967 में शामिल कर लिया था। रूस में बने सुखोई तथा फ्रांस मिराज 2000 के भारतीय संस्करण का निर्माण एचएएल लगभग दो से अधिक दशकों से कर रही है। एचएएल मिग21 लड़ाकू विमानों का आधुनिकीकरण कर चुकी है, साथ ही जगुआर जहाज का आधुनिकीकरण भी किया जाना तय हुआ है।

एचएएल में बने 4थीं पीढ़ी के तेजस मार्क 1 को भी भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा चुका है, वहीं तेजस के दूसरे उन्नत संस्करण तेजस मार्क1A तथा मार्क2 पर काम जारी है। भारत स्वदेशी निर्मित 5.5वी पीढ़ी के एएमसीए (एमका) लड़ाकू जहाजों पर भी काम चालू कर चुका है। भारत एएमसीए के साथ ही तेजस के नेवी संस्करण जैसा ही ओमनी रोल ORCA विमान भी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वायु सेना पहले ही मानव रहित ड्रोन विमान रुस्तम1 व 2 अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। इसके अलावा अति उन्नत मानव रहित विमान (यूसीएवी) औरा (एयूआरए) का विकास भी जारी है। डीआरडीओ तथा इसकी अन्य शाखाएं मिलकर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एवं कंट्रोल सिस्टम (एईडब्ल्यूस एंड सीएस) बना चुके हैं। भारत निर्मित एलसीएच हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान के बाद आज 162 अन्य हेलीकाप्टर आदेश पर बनने हैं। भारत में स्वनिर्मित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एलयूएच ध्रुव भी भारतीय सेनाओं में अपनी जगह बना चुका है। हाल ही में एचएएल ने मानव रहित खोजी हेलीकाप्टर NRUAV का सफल परीक्षण किया है।

भारतीय वायुसेना भारत में ही निर्मित रडारों का उपयोग भी कर रही है। बीईएल ने भारत में निर्मित रडारों की एक पुरी श्रंखला तैयार कर दी है जिनमें मुख्य हैं– इंद्रा1, इंद्रा2, 3D कार श्रेणी का रोहिणी रेडार, राजेन्द्रा रेडार मुख्य है। दूसरी ओर भारत में निर्मित एचएएल तेजस के लिए भी बीईएल, उत्तम नामक AESA रेडार भी बना रही है। आश्लेषा, अरुद्रा, अश्विनी आदि रेडार अभी वायुसेना में शामिल किए जाने हैं। इनके परीक्षण निरन्तर गतिमान हैं। बीईएल द्वारा डिजिटल मोबाइल रेडियो रिले (डीएमआरआर), मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल (एमसीटी), आईपी रेडियो, वीएचएफ व यूएचएफ रेडियो आदि का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

थल रक्षा में स्वायत्तता– भारत की थल सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना ने सैनिको के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे "फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री सैनिक एक प्रणाली के रूप में" के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यह अपने बखतरबंद, तोपखाने और उड्डयन शाखाओं के लिए नए संसाधनों का संग्रह एवं सुधार भी कर रहा है। हमारी थल सेना की जमीनी इकाइयां (इन्फेंट्री) भारत में ऑर्डिनेंस फैक्टरी द्वारा निर्मित

इंसास राइफल की जगह रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के तहत ली गई एके–203 का उत्पादन करने जा रही है। भारत में ही लगभग 7.5 लाख की संख्या में आर्डिनेंस फैक्टरी द्वारा किया जाएगा। थल सेना स्वदेशी स्नाइपर राइफल 'विध्वंसक' को 2007 में ही अपना चुका है।

भारत की आर्डिनेंस फैक्ट्री स्वदेशी निर्मित एमबीटी अर्जुन टैंक का निर्माण पहले ही कर चुकी है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति व प्रणालियों के उद्‌गम बीईएल ही रही है। एमबीटी अर्जुन भारत का मुख्य युद्धक टैंक है। इस पर भारत में ही निर्मित अत्याधुनिक मजबूत मिश्रधातु से निर्मित 'कंचन' नामक कवच से लगाया गया है। भारतीय सेना स्वदेशी निर्मित होवित्जर तोप धनुष का सफल मूल्यांकन कर देश सेवा के भर्ती कर चुकी है। भविष्य में इसी निजी उद्यम द्वारा निर्मित बी–52 हॉवित्जर तोप के भर्ती किये जाने की भी आशंका है। मल्टी बेरल रॉकेट लांचर 'पिनाका' प्रणाली भी थल सेना के बेड़े की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं वायु सुरक्षा शाखा में रूस से खरीदे गए शिल्का गन को बीईएल ने उन्नत किया है। एके11 स्नाइपर तथा एटी5 स्पेंडरेल का निर्माण सबसे करीबी मित्र रूस से लाइसेंस लेकर भारत मे ही मेक इन इंडिया के आधार पर बनाया जा रहा है। बीईएल के रेडार हमेशा भारतीय थल सेना के साथ मिलकर देश सेवा में अग्रणी रहें हैं। राजेन्द्र रेडार (आर्मी आकाश वायु रक्षा प्रणाली के लिए), स्वाति, 3D–टीसीआर, समयुक्ता वारफेयर सिस्टम, भरनी, युद्ध क्षेत्र चौकसी रेडार (बीएफएसआर) आदि रेडार स्वदेश में ही निर्मित तथा सेवारत कर गए है। AD&TCR, मल्टी मिशन रेडार, दीवाल के पार देखने वाले रेडार तथा धरती में बमखोजक रेडार अभी अपनी विकासशिल अवस्था में है। भारतीय थलसेना बीईएल द्वारा निर्मित संचार संसाधनों जैसे ट्रांस्पोर्टेबल सेटेलाइट टर्मिनल, स्टार्स वी, वीएचएफ एवं यूएचएफ रेडियो, सेटेलाइट संचार एंटेना आदि का उपयोग निरन्तर करती आ रही है।

नौसेना में रक्षा आत्मनिर्भरता – भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण में सदैव अग्रणी रही है। इसके परिणामस्वरूप हमने हाल ही में पहली टारपीडो प्रणाली मारीच को बनाया है जिसे डीआरडीओ द्वारा डिजाइन तथा बीईएल द्वारा निर्मित किया गया। इसके अलावा विभिन्न सोनार और अगली पीढ़ी के कम आवृत्ति के सोनार को शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। युद्ध प्रबंधन प्रणाली, सोनार, रेडार जैसे रेवती, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार प्रणाली आदि को भी बीईएल, डीआरडीओ के मार्गदर्शन में देश में ही निर्मित कर रही है। एक संयुक्त और सहकारी तरीके से प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न चुनौतियों के साथ योजनाबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। प्रमुख युद्धपोत 'विक्रांत' का निर्माण कार्यक्रम प्रगति पर है। आने वाले समय में तेजस लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण इसकी शोभा बढ़ाएंगे। अत्याधुनिक विमानवाहक पोत 'विशाल' तथा ट्विन इंजिन डेक बेस्ड फाइटर (TEDBF) विचार निरन्तर जारी है।

आईएनएस कोलकाता श्रेणी के तहत चार स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक जहाज बनने थे जिसमें से 3 राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इन पर भी बीईएल द्वारा बनाए गए रेडार सुसज्जित हैं। आईएनएस विशाखापटनम श्रेणी के अन्य तीन अत्याधुनिक विध्वंसक जहाज सामुद्रिक परीक्षण से गुजर रहे हैं तथा चौथा अभी बन रहा है।

आईएनएस कामोर्टा श्रेणी के तहत बने चार कॉरवेट जहाज बना लिए गए हैं। ये चारों बीईएल द्वारा बनाये रेवती में Lynx फायर कंट्रोल रेडार लगे हुए हैं।भारतीय आर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा उन्नत एन्टी मिसाइल सिस्टम कवच को इस सुसज्जित किया गया। इस श्रेणी का अंतिम जहाज आईएनएस कवरत्ती अक्टूबर, 2020 में नौसेना बेड़े में शामिल हुआ है। पनडुब्बी विनिर्माण में आईएनएस कलवारी श्रेणी के तहत डीजल इलेक्ट्रिक पंडुब्बियों का निर्माण कार्य जारी है। आईएनएस अरिहंत श्रेणी की पहली नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाली पंडुब्बी भारत में बन कर नेवी को सुपुर्द की जा चुकी है। इसके बाद 3 पंडुब्बी और बनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के पांच स्थायी सदस्य देशों के अलावा मात्र भारत एक ऐसा देश है जो कि नाभिकीय ऊर्जा से चलित पनडुब्बियां बना पाया है। इनमें भी बीईएल द्वारा निर्मित USHUS सोनार तथा भारत में ही निर्मित पंचेन्द्रिय सोनार लगा है। बीईएल द्वारा निर्मित रेवती तथा Lynx रेडार के अलावा RAWL रेडार तथा अजंता मार्क2 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी भारतीय जहाजों पर लगे हैं। बीईएल स्वदेशी

निर्मित सोनार हम्सा में लगभग 70 प्रतिशत स्वदेशी निर्मित उपकरणों के उपयोग लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है।

भारत का वायु रक्षा तंत्र व मिसाइल कार्यक्रम –

भारत की विभिन्न मिसाइलें उसकी सुरक्षा प्रणाली का बेहद अहम हिस्सा हैं। अग्नि श्रेणी की सभी मिसाइल को सम्मिलित कर लिया गया है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है।

पृथ्वी रेंज की मिसाइलें भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की है और भारतीय सेना में इसे शामिल किया जा चुका है। भारत के एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पूर्ण रुप से स्वदेश में निर्मित पहला बैलेस्टिक मिसाइल है।

शौर्य मिसाइल– सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल शौर्य का सफलतापूर्वक परीक्षण यह मिसाइल जमीन के अलावा पानी के भीतर से भी छोड़ी जा सकती है।

धनुष मिसाइल– धनुष मिसाइल को नौसेना के इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है और यह 350 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद सकती है। ये पृथ्वी मिसाइल का नौसेना संस्करण है।

ब्रह्मोस मिसाइल– सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मार्च 2012 को हुए अभ्यास परीक्षण के बाद सेना के तीनों अंगों में पूरी तरह तैनात हो गई है। इस तरह की कोई और मिसाइल अभी तक विश्व में विकसित नहीं की गयी है।

सागरिका मिसाइल– भारत के पास सागरिका नाम की ऐसी मिसाइल भी है जो समुद्र से दागी जा सकती है और जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।इस तरह की मिसाइलें चंद ही देशों के पास हैं।

नाग मिसाइल– दागो और भूल जाओ (Fire and forget) के सिद्धांत पर विकसित नाग एक टैंक रोधी मिसाइल (anti & tank missile) है। नाग मिसाइलों का हेलीकाप्टर में प्रयोग किया जा सकने वाला संस्करण भी विकसित किया जा चुका है जिसे हेलिना के नाम से जाना जाता है। इसे एचएएल द्वारा विकसित ध्रुव हेलीकाप्टरों में लगाया गया है इन मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए विशेष वाहन नामिका (NAMICA – Nag Missile Carrier) का भी विकास किया गया है।

प्रहार, निर्भय मिसाइल, बीवीआर अस्त्र के अलावा सूर्य मिसाइल भारत एक अंतर–महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) विकसित करने का प्रयास कर रहा है जो एक MIRV मिसाइल होगी यह मिसाइल 2500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 8000 – 10000 किलोमीटर। ये अभी डीआरडीओ के अंतर्गत विकासशील अवस्था में हैं। इन सब के बाद भारत ने अगस्त, 2020 के बाद मात्र 35 दिनों में मिसाइलों के 9 सफल परीक्षण करके दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेसर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल के दो बार सफल परीक्षण किए गए। पृथ्वी 2, शौर्य, ब्रह्मोस के 450 किलोमीटर संस्करण, रुद्रम नामक टारपीडो तथा एन्टी रेडार मिसाइल का सफल परीक्षण शामिल है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण तथा भारत की आत्मनिर्भरता पर किताब लिखी जा सकती है। इसे एक लेख के रूप में संकलित करना कठिन परन्तु रोमांचकारी अनुभव रहा है। लेख में प्रस्तुत जानकारियां सामान्य जनमंच पर उपलब्ध है।

नितेश तिवारी
संकर्म संयोजन, रेडार, गाजियाबाद यूनिट

आत्मनिर्भरता के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था - एक विमर्श

आत्मनिर्भर शब्द हममें से किसी के लिए भी नया नहीं है। यह ठीक "अपने पैरों पर खड़े होने" वाली उस सीख की तरह है जिसे हम बचपन से अपने माता पिता से सुनते हुए बड़े होते है। व्यक्ति की तरह समाज और देश भी आत्मनिर्भर बनता है, यह कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन समाज, देश, देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यकताओं को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरु की गई पहल 'आत्मनिर्भर भारत' बिल्कुल उपयुक्त लगती है। अपने निजी जीवन में जिम्मेदारियां उठाने का अहसास आत्मनिर्भरता का एक पहला कदम होता है जो हमें जिम्मेदार बनने, स्वतंत्र बनने की ओर ले जाता है और हम न केवल स्वयं को बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी सहजता से उठाने लगते है। वैसे तो हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक की यात्रा में कई दौर से गुजरते है लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वह है अपनी क्षमता निर्मित करना क्योंकि यही सक्षमता हमें आत्मनिर्भर बने रहने में हमारा मूलमंत्र बनती है । यह हम सभी के जीवन में होता है, इसे हर व्यक्ति देखता है, उससे गुजरता है और महसूस करता है। आइए, हम इसी परिघटना को अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं।

आत्मनिर्भरता – वैयक्तिक या सामूहिक

हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आज जब दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ इतनी ज्यादा अंतर्संबंधित है तो क्या सचमुच कोई देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है? मेरे विचार से इसका उत्तर ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इसका उत्तर ना है तो फिर इस दिशा में प्रयास क्यों किए जा रहे है? दरअसल यहाँ हमें इन दोनों बातों को गहराई में समझना होगा। इसके लिए हमें एक बार फिर अपने निजी जीवन का उदाहरण लेना होगा। आज आप अपने पैरों पर खड़े है, समृद्ध है, जिम्मेदार है, पर क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, क्या आप पूरी तरह आत्मनिर्भर है?

इस सवाल का जवाब हां और ना दोनों हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर आप सोचें कि सुबह से लेकर रात तक आपने जिन सामानों या सेवाओं का उपयोग या उपभोग किया है, ये आपकी बनाई हुई तो नहीं है, तो निश्चय ही आपका जवाब होगा कि हाँ, इस मामले में तो मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी और द्वारा बनाई गई चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। परंतु अगर इसी बात को अगर इस नजरिए से देखें कि सुबह से रात तक आपने जितने सामान या सेवाओं का इस्तेमाल किया है, उन्हें आपने अपनी कमाई से, अपने संसाधनों से किया है, तो क्या आपको आत्मनिर्भर नहीं कहा जाएगा। इस उदाहरण से हम यह समझते है कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम हर चीज स्वयं अपने हाथों से बनाएँ।

ठीक इसी संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को समझने की जरूरत है। आज अगर हम दुनिया के समृद्ध देशों (अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्विटजरलैंड आदि) पर नजर डाले तो देखेंगे कि हम इन्हें इसलिए आत्मनिर्भर नहीं मानते है कि ये देश हर चीज खुद बनाते है बल्कि इसलिए मानते है कि ये देश ज्यादातर चीजें बनाने की क्षमता रखते हैं। चीजों को या उसके कुछ प्रतिशत हिस्से को खुद अपने देश में बनाना या किसी और देश में बनवाना, यह उस कारोबार–विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ऐसे देश में उस सामान या सेवा को डिजाइन से लेकर उत्पादन करने तक की क्षमता है की नहीं? और इस क्षमता के मामले में सभी विकसित और समृद्ध देश इस जरूरत को सौ प्रतिशत पूरा करते है।

अब बात करते है अपने देश भारत की, यह सर्वविदित है कि आजादी के दशकों बाद भी, एक लंबे समय तक भारत कृषि प्रधान देश रहा है। औद्योगिकीकरण की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही पर पिछले कुछ दशकों में इसने अच्छी रफ्तार

पकड़ी है। इसका श्रेय, देश की सभी सरकारों की प्रगामी नीतियों और उन उद्यमियों को जाता है जिन्होंने देश को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज पूरी दुनिया में भारत को और भारतीयों की काबिलियत को आदर की नजर से देखा जाता है। परंतु क्या यह काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे सात दशक युवा देश को अगर दो सौ से ढाई सौ साल पुराने और अनुभवी समृद्ध देशों की लीग में अगर आना है तो हमें वास्तव में बहुत तेजी से विकास करना होगा।

आत्मनिर्भर भारत मिशन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक अहम हिस्सा है। इस मिशन में देश को कुछ ऐसे उच्च प्राथमिकता और अधिक प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करनी होगी ताकि सम्मिलित प्रयासों से जल्द अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। सभी लोगों की भागीदारी ही इस मिशन को सफल बना सकती है।

जैसा कि पहले कहा गया कि हर चीज खुद बनाना आत्मनिर्भरता की निशानी नहीं है, अपितु चीजों को बनाने की क्षमता रखना आत्मनिर्भरता की निशानी है। इसलिए, यह बहुत जरूरी है कि पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश की डिजाइन और विकास करने की क्षमता विकसित करने की और प्रयास किया जाए। हाल के कुछ विशिष्ट घटनाक्रम – जैसे सीमा पर तनाव, कोविड–19 महामारी के चलते हमारी आयात से जुड़ी आपूर्ति में व्यवधान आदि ने देश को गंभीरतापूर्वक सोचने पर मजबूर किया है कि देश का विशिष्ट क्षेत्रों में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए देश को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों रणनीतियों पर एक साथ काम करना होगा। अल्पकालिक रणनीतियों के लिए हो सकता है कि देश को कई विकसित देशों से कई प्रकार की मदद लेनी पड़े लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। मूलभूत अनुसंधान, व्यावहारिक अनुसंधान और अभियांत्रिकी में स्थायी रूप से सक्षमता विकास करना बहुत जरूरी है ताकि देश में डिजाइन और विकास की क्षमता को प्रोत्साहन मिले।

आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था

क्या आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था में प्रगति लाएगी? इस सवाल का जवाब भी हां या ना हो सकता है। यदि आप खाड़ी के देशों का उदाहरण ले तो देखेंगे कि ये देश सिर्फ कच्चे तेल के संसाधनों की वजह से इतने अधिक अमीर है। उनकी अर्थव्यवस्था केवल एक संसाधन के बलबूते सालों से टिकी हुई है। अन्य क्षेत्रों में वे आत्मनिर्भर है या नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वहीं अगर आप दुनिया के आत्मनिर्भर और समृद्ध देशों जैसे जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी,चीन आदि को देखें तो उत्तर जरूर हां मिलेगा। ये वे देश है जिन्होंने लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है। चूंकि भारत भी अपने आप में एक संपूर्ण देश है, इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में आत्मनिर्भरता का बड़ा योगदान निश्चित रूप से होगा। यही कारण है कि इस बात को मिशन का रूप देने की रणनीति बनाई जा रही है। यहां हम सब के जीवन से जुड़े एक व्यावहारिक उदाहरण को लेते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपने जीवन में जब भी घर बनाना चाहते होंगे तो आपकी पहली वरीयता यही होगी कि घर बनाने में आपकी खुद की जमा पूंजी लगी हो। परंतु मध्यमवर्गीय हर व्यक्ति अपनी इस जरूरत को पूरा करने में हमेशा कुछ न कुछ पूँजी का अभाव महसूस करता है, इसलिए वह बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेकर अपनी इस महात्वाकांक्षी योजना को पूरा करता है। क्या यह गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ठीक इसी तरह हम आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं फिर चाहे हमें अपने मैत्रीपूर्ण समृद्ध देशों से पारस्परिक हित के शर्तों व निबंधनों पर मदद क्यों न लेनी पड़े। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनेक विकसित देश प्रौद्योगिकी–सघन कई क्षेत्रों में हमसे कई गुना आगे हैं, यदि ये देश पारस्परिक सहमत शर्तों पर अपनी कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ हमसे साझा करते हैं तो हमें यह स्वीकार्य होना चाहिए। ठीक इसी तरह बाहर की कंपनियां यदि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफ.डी.आई. के माध्यम से हमारे देश में निवेश करती हैं तो यह हमारी आत्मनिर्भरता के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक होगा।

इन सफल विदेशी कंपनियों की मौजूदगी न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाती है, बल्कि उनसे हमारे होनहार इंजीनियरों और मैनेजरों को पेशेवर कार्यशैली

और कौशल सीखने का भी भरपूर मौका मिलता है। हो सकता है कि विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करने का यह विचार यानी उनकी पूंजी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगाना आपको विरोधाभासी लगे, पर हमें यह भी समझना होगा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है। बाहरी देशों की किसी भी तरह की मदद को हमें अवसर की तरह देखना होगा जो हमें हमारे मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को हासिल करने में मदद कर सकता है।

देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में, स्वदेशीकरण एक मुख्य कड़ी है। स्वदेशीकरण पर जोर देश के उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान करता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उच्च प्राथमिकता और उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों की पहचान करें और उसमें सभी भागीदारों को साथ लेकर, स्वदेशीकरण के अभियान को मिशन के रूप में पूरा करें। जरूरत इस बात की है कि देश में एक ऐसा परितंत्र तैयार हो, जहां उद्यमियों के पास उनके आकार से संबंध न रखते हुए, सभी आवश्यक संसाधन और समर्थन प्राप्त हो ताकि वे अपने नवाचार और नए विचारों से अपने प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकें। स्टार्ट–अप इंडिया, ई.आई.आर. (इंटरप्रोन्योर्स इन रेसिडेंस), मुद्रा योजना, अटल उद्भवन केंद्र, आईडेक्स आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में इस दिशा में काम शुरु किए गए हैं, परंतु अभी बहुत कुछ होना बाकी है।

स्वदेशीकरण की भूमिका

स्वदेशीकरण की इस मुहिम में कुछ बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है ताकि स्वदेशीकरण के प्रयास को सही दिशा मिल सके। यह जरूरी नहीं कि हमारा स्मार्ट फोन कहां बनता है पर यह बहुत जरूरी है कि उसमें इस्तेमाल होने वाला आपरेटिंग सिस्टम या तरह–तरह के ऐप या साफ्टवेयर भारतीय हों। इसी तरह चौकसी कैमेरे का हार्डवेयर कहां बनता है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसमें इस्तेमाल होने वाला फेस रिकग्नीशन साफ्टवेयर, डेटा रिकार्डर, डेटा स्टोर करने वाला सर्वर आदि जो स्वदेशी हों। फोन और कैमेरा के बाहरी उपकरण देश में बनाकर हम खुद को आत्मनिर्भर नहीं कह सकते। जरूरी यह नहीं है कि देश में मेट्रो ट्रैन की बोगियां कहां बनती है, जरूरी यह है कि इन ट्रेनों को नियंत्रित करने वाला हार्डवेयर और साफ्टवेयर हमारे देश में बनता है कि नहीं। अगर हमारे देश के पास ऐसे जटिल हार्डवेयर और साफ्टवेयर को डिजाइन करने और उन्हें विकसित करने की क्षमता है तो यकीन मानिए बोगी बनाने की क्षमता आज नहीं तो कल देश विकसित कर ही लेगा।

आज जब समय सीमित है और साधन प्रचुर, तो यह बहुत जरूरी कि भारत स्वदेशीकरण की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और अपने मूल लक्ष्य (आत्मनिर्भरता) की तरफ तेजी से आगे बढ़े। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शरीर का स्वदेशीकरण हो या न हो, आत्मा का स्वदेशीकरण होना बहुत जरूरी है।

अंतरिक्ष कार्यक्रमों, मिसाइल प्रोग्रामों में देश ने जो उपलब्धियाँ हासिल की है उससे पूरा विश्व अचंभित है जबकि ये प्रौद्योगिकी–गहन क्षेत्र हैं। वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता देश की तरह ही देखा जाता है। अगर इस क्षेत्र में हमारा कुछ खास योगदान नहीं है तो हमें स्वयं को हारा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसका सकारात्मक पहलू देखें कि उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कॉग्निटिव रेडियो, क्लाउड कंप्यूटिंग, सायबर सुरक्षा, मानव–रहित मिशन आदि) ने हमें सुनहरा मौका दिया है कि भारत इस दौड़ में वहीं से शुरु करे जहां से विकसित देश शुरु कर रहे हैं। भारत में इन क्षेत्रों में सफल होने की क्षमता है और हम यह जरूर कर सकते हैं। हमारी घरेलू मांग, जनसांख्यिकी, बुनियादी ढांचा और डिजिटलीकरण के प्रयास हमें ताकत और अवसर दोनों दे रहे हैं। देश का युवा उद्यमी वर्ग इस बात को भलीभांति समझता है।

ताली दो हाथों से बजती है लेकिन दोनों हाथों का तालमेल ही सही आवाज तय करता है। इसी तरह, मांग और आपूर्ति का तालमेल भी देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करता है। भारत में हर क्षेत्र में माल और सेवाओं की मांग बहुत अच्छी है, अगर इनकी आपूर्ति स्वदेशी साधनों से ही हो जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए सोने पर सुहागा साबित

होगा। यही कारण है कि देश आज हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने आपको आत्मनिर्भर देखता चाहता है।

देश की इस मुहिम में, देश के उपभोक्ता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रौद्योगिकी या उत्पाद, कभी भी पहली बार में 100% उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यदि स्वदेशी सामान या प्रौद्योगिकी 100% परिपूर्ण न भी हो और उसे अपने देश के उपभोक्ता की स्वीकृति मिले तो देश के निर्माताओं, उत्पादकों और डिजाइनरों को हौसला मिलेगा, वे प्रोत्साहित होंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने प्रयोक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का अवसर मिलेगा। स्थापित बाजार में यही प्रयास धीरे–धीरे मांग और आपूर्ति के चक्र को संपूर्णता की ओर ले जाता है।

अगले कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर बनने का सपना इन्हीं पगडंडियों से होकर साकार होगा।

रंजीत करमचंदानी
सीएमडी के स्टाफ अफसर
कॉर्पोरेट ऑफिस

'ज्ञ' से ज्ञान

हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। इनमें से एक अदभुत वर्ण है संयुक्त अक्षर 'ज्ञ' जो कि 'ज' और 'ञ' के योग से बना है। दोनों ही चवर्ग के अक्षर है। 'ज' चवर्ग दूसरे क्रम में हैं और इस संयुक्त अक्षर में बिना 'अ' के प्रयोग है, यानि कि आधा 'ज'। 'ञ' इसी वर्ग का पांचवा अक्षर है। 'ञ' से शुरु होने वाला कोई शब्द नही होता पर यह कई शब्दों के अंदर अवश्य प्रयोग होता है जैसे कि व्यञ्जन, सञ्योग। कालांतर में संस्कृत से हिन्दी में आने पर 'ञ' के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है।

'ज्ञ' के उच्चारण में आमतौर पर विरोधाभास है और इसका उच्चारण 'ग्य' किया जाता है। सही उच्चारण के लिये इसके अक्षरों को अलग–अलग जानना होगा। ज् का उच्चारण तो सभी जानते हैं, 'ञ' का जान लेते हैं।

च वर्ग के अक्षरों को बोलने पर जीभ तालु से चिपकती है। 'च' से 'ञ' तक बोलने पर ध्यान देने से पता चलता है कि तालु पर जीभ पीछे से आगे की ओर जा रही है। अभ्यास करके सही उच्चारण किया जा सकता है जो कि निकटतम लिखने योग्य होगा 'न्य'। इस तरह 'ज्ञ' का सही उच्चारण लगभग 'ज्न्य' हुआ, जिसको अंग्रेजी में आमतौर पर 'Jna' लिखा जाता है।

यह अक्षर हिंदी के अलावा भी अन्य भाषाओं में प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं –'ज्ञान', जिसका अर्थ है जानना या स्वयं को जानना।

- मराठी–'ज्ञ' का उच्चारण 'द्न्य' 'Dna', ज्ञान– 'द्न्यान' 'Dnan'
- कन्नड– 'ज्ञ' का उच्चारण ग्न्य Gna, ज्ञान– 'ग्न्यान' 'Gnan'
- अंग्रेजी– 'Gn' का उच्चारण ग्न (ग् मूक), Gnostic यानि– ज्ञानी
- अंग्रेजी– 'Kn' का उच्चारण क्न (क् मूक), Knowledge– ज्ञान
- जर्मन– 'Gn' का उच्चारण ग्न (ग् मूक), Gnostiker– ज्ञानी
- फ्रेंच– 'Gn' का उच्चारण ग्न (ग् मूक), Gnostique– ज्ञानी

इनके अलावा भी विश्व की बहुतेरी भाषाओं में यह अक्षर संयुक्त अक्षर के रुप में प्रयोग हुआ है।

प्रवीण कुमार
अपर महाप्रबंधक (डी एंड ई व विपणन)
नवी मुंबई

स्वदेशी अपनाएँ, भारत को आत्मनिर्भर बनाएँ

आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जीवन में अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर न होना। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें अपनी आजीविका के लिए दूसरों से मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को स्व–संपूर्ण और आत्म–निर्भर होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर होता है, जीवन में कभी भी प्रगति या सफल नहीं हो सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत – भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड–19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इसके दूरगामी दुष्प्रभावों से बचते हुए भारत को एक समृद्ध देश बनाना है। यह योजना 12 मई 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार, देश के लोगों को 20 लाख करोड़ रुपये की राहत पैकेज की घोषणा की गई थी।

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2020 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' की संकल्पना में विश्वास करता है। प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए भारत दुनिया की प्रगति में भी अपना योगदान देता है।

वर्तमान समय में सरकार ने "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों के आयात में कटौती का भी निर्णय किया है। इसमें फर्नीचर, फुटवियर, एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्युटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं।

9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री जी ने घोषणा की कि, "आत्मनिर्भर भारत" मुहिम के तहत देश में रक्षा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 101 उपकरणों की आयात पर रोक लगाई जाएगी। इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भर बनने के बड़े अवसर मिलेंगे। प्रचुर अवसर– जैसा कि हम सभी जानते है, अभी हमारा देश कोविड–19 महामारी से गुजर रहा है। इस संकट ने हमारे देश को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इस भयानक महामारी में हमने सिद्ध कर दिया है कि चाहे हमारे देश में कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाये, हम देश के साथ है और हम देश को किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं होने देंगे।

हम अभी तक कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर आदि जैसे चीजों का उत्पादन कर चुके है। हमारे देश में किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। पहले हमारे देश में पीपीई किट, वेंटिलेटर और सैनिटाइजर आदि का बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन होता था। लेकिन ऐसी भयानक स्थिति में खुद पर निर्भर होने का बहुत ही बड़ा उदाहरण हमने अन्य देशों को दिया है। इनका स्वयं उत्पादन करना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक अहम और पहला कदम है और यह सफल भी हुआ है। इससे हमारा देश दूसरे देशों की नजरों में और भी ऊँचा हो गया है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के लाभार्थी – किसान, गरीब नागरिक, प्रवासी श्रमिक, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मछुआरे, पशुपालक, मध्यम वर्ग के उद्योग, किरायेदार, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जैसे लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

आत्मनिर्भरता के फायदे –

भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं में काम कर रहा है जैसे –

- नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।
- कारखानों में कई नई तकनीकों या नई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।
- सुई से लेकर जहाज तक के उत्पादन की योजना बनाई जा रही है।
- कृषि क्षेत्र को पहले से अधिक महत्व दिया जा रहा है और उनकी स्थिति में सुधार किया जा रहा है।
- शिक्षा नीति में बदलाव किए जा रहे हैं।
- अस्पतालों के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि सभी उपचार केवल भारत में ही संभव हों।
- भारत अब डिजिटल इंडिया बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां हर क्षेत्र में ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

आत्म निर्भर भारत मिशन के चरण– मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा –

पहला चरण – इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

दूसरा चरण – इस चरण में फर्नीचर, फुटवेयर और एयर कंडीशनर, पूंजीगत सामान तथा मशीनरी, मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल आदि शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य इन पाँच स्तंभों से हासिल होगा –

1. **अर्थव्यवस्था –** जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो।
2. **अवसंरचना –** ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने।
3. **प्रौद्योगिकी –** 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणाली।
4. **गतिशील जनसांख्यिकी –** जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी।
5. **मांग –** भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना जाएगा।

आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें अनगिनत चुनौतियों से पार पाना होगा। सबसे पहली चुनौती तो निवेश की ही है। भारत में छोटे और मझोले उद्यमियों के पास अक्सर निवेश के लिए पूंजी नहीं होती। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहन देने की विशेष जरूरत है। इसके लिए अनुकूल नीतियों का निर्धारण करने की आवश्यकता है जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ निर्यात केंद्र भी बन सके तभी भारत चीन जैसे देशों के सामने स्वयं को स्थापित कर पाएगा।

रवि शंकर सेठ
प्रबंधक आई टी
क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

वीर कभी बड़े मौकों का इंतजार नहीं करते हैं,
छोटे मौकों को ही बड़ा बना देते हैं।
– सरदार पूर्णसिंह

भारत सरकार की सार्थक पहल - स्टार्टअप इंडिया

सफलता की तरफ देश का नया आगाज़, उद्देश्य यही, युवा शक्ति का हो विकास

देश के हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, उस सपने के साथ उसके दिल में कुछ विचार भी होते हैं। कुछ लोगों में ऐसे विचार हर दिन आते हैं और शाम होते–होते लुप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को साकार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप की योजना बनाई है।

स्टार्टअप इंडिया..... आर्थिक विकास की कार्य योजना की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 69 वें स्वतंत्रता दिवस पर स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा की, जिसमें भारत की प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी को ष्भारत और मानवता के लिए कुछ नया करने की अधिक ताकत और प्रेरणाष् प्रदान करने की आकांक्षा व्यक्त की थी और उन्होंने एक वर्ष के भीतर स्टाअर्टअप इंडिया कार्य योजना लांच कर दिया था।

भारतीय स्टार्टअप परितंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, कई स्टार्टअप, उद्यमी और अभिनव प्रयास करने वाले नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। सरकार देश की रक्षा और सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए नव प्रवर्तनकर्ताओं को आगे लाने के लिए जोर दे रही है।

क्या है स्टार्टअप ?

स्टार्टअप एक नई कंपनी या संस्थान होता है, जिसको शुरू करने के बाद उसे विकसित किया जाता है। आमतौर पर स्टार्टअप नई कंपनी, संस्था या फर्म शुरू करने को कहा जाता है, जिसे कोई युवा स्वयं या दो तीन लोगों के साथ मिलकर शुरू करता है। आमतौर पर इसे शुरू करने वाला व्यक्ति इसमें पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है। इस उद्यम में किसी ऐसे उत्पाद या सेवा को पेश किया जाता है, जो बाजार में पहले से उपलब्ध नहीं होता है।

स्टार्टअप इंडिया के तीन स्तंभ

स्टार्टअप इंडिया की पहल निम्नलिखित तीन स्तंभों के इर्द–गिर्द घूमती है –

- सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग
- वित्त पोषण और प्रोत्साहन
- उद्योग–अकादमिक साझेदारी और इन्क्यूबेशन ।

हर स्टार्टअप एक उद्यम है लेकिन हर उद्यम स्टार्टअप नहीं हो सकता।

स्टार्टअप वह उद्यम होता है जिसमें जोखिम ज्यादा होता है। स्टार्टअप के लिए, नवाचार नींव है। अधिकांश सफल स्टार्टअप मौजूदा समस्याओं के लिए अभिनव समाधान ढूंढ रहे हैं। इसलिए, स्टार्टअप का उद्देश्य नई चीजों को बनाना है। स्टार्टअप तेज विकास पर केंद्रित होते हैं और इनके पास अपने बाजारी मूल्य या उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भविष्य के लक्ष्य और योजना नहीं होती है। प्रौद्योगिकी आमतौर पर स्टार्टअप का मुख्य कारक होता है । नई तकनीकों के बिना स्टार्टअप के लिए तेजी से विकास करना और उंचाई हासिल करना संभव नहीं है।

अगर कोई व्यक्ति ऐसा उद्यम करता है जिसमें जोखिम कम रहता है और वह ऐसी सेवा अथवा उत्पाद को ग्राहकों के

समक्ष पेश करता है जिसमें कोई नवीनता नहीं होती और उसका उद्देश्य पहले से स्थापित बाजार में अपना शेयर हासिल करना होता है, तो ऐसे उद्यम को स्टार्टअप नहीं कहा जा सकता।

रक्षा क्षेत्र में स्टार्ट अप की भूमिका– गृह मंत्रालय के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी.), जो एक विशेष भारतीय बल इकाई है, ने स्वैट (विशेष हथियार और रणनीति) टीमों के साथ बंधक स्थितियों और आतंकी हमलों से निपटने के लिए स्टार्टअप द्वारा स्मार्ट हथियारों और उपकरणों का लाभ उठाने की योजना बनाई है जिसके तहत ऐसे स्टार्टअप को कई विशेष अवसर और अनुलाभ भी दिए जा रहे हैं ।

रक्षा उत्कृष्टता (आईडेक्स) की पहल– रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की मदद के लिए नई तकनीकों को खोजने के लिए, अप्रैल 2018 में रक्षा उत्कृष्टता (आइडेक्स) योजना शुरू की। रक्षा क्षेत्र में पहली बार अनूठी पहल की गई है जिसमें रक्षा उत्कृष्टता (आइडेक्स) के माध्यम से डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चौलेंज (डिस्क) के तहत रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध का परिवेश तैयार किया गया है। इससे इस रक्षा कार्यक्रम की प्रमात्रात्मकता और गुणवत्ता दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना

स्टार्टअप इंडिया की कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

3 साल के लिए स्टार्टअप को कर में छूट
स्व–प्रमाणन पर आधारित अनुपालन
पेटेंट शुल्क पर छूट और फास्ट–ट्रैक पेटेंट परीक्षा
पूंजी लाभ पर कर छूट
स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद के नियमों में छूट
स्टार्टअप के लिए जल्द निकास मार्ग
निष्पक्ष बाजार मूल्य से ऊपर के निवेश के लिए कर छूट
स्टार्टअप को वित्त पोषण का समर्थन प्रदान करने के लिए 4 वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा 2500 करोड़ के शुरुआती कोष और 10000 करोड़ के कुल कोष की स्थापना
स्टार्टअप के लिए ऋण अदायगी गारंटी
उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का शुभारंभ
निजी क्षेत्र के विशेषज्ञता का दोहन
राष्ट्रीय संस्थानों में नवाचार केंद्रों की स्थापना
सात नए अनुसंधान पार्क
जैव प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप को बढ़ावा देना
छात्रों के लिए कार्यक्रम
वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चौलेंज
पेटेंट आवेदन शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट

स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य– स्टार्टअप इंडिया योजना रोजगार और धन सृजन के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत परितंत्र का निर्माण करना है। इस पहल के तहत स्टार्टअप इंडिया का एक पोर्टल तैयार किया गया है, जो स्टार्टअप, इनक्यूबेटर्स, मेंटर्स, एंजेल फंड्स, वेंचर निधि आदि की पहचान करेगा और इनसे संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। स्टार्टअप इंडिया योजना रोजगार और धन सृजन के लिए भारत सरकार की एक पहल है। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य उत्पादों और सेवाओं का विकास और नवाचार करना है और भारत में रोजगार दर को बढ़ाना है।

भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का उद्देश्य दुनिया के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का विकास करना है।

स्टार्टअप के पंजीकरण की प्रक्रिया

⇨ 7 वर्ष तक और बायोटेक्नोलॉजी के लिए पंजीकरण/ पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक स्टार्टअप शुरु होता है।

⇨ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पंजीकृत साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी के रूप में शुरु किया जा सकता है।

⇨ किसी भी वित्तीय वर्ष का कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ हो ।

⇨ अस्तित्व में पहले से ही एक व्यापार को विभाजित या पुनर्निर्माण कर किसी यूनिट का गठन न किया गया हो।

⇨ नवाचार, विकास या उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के सुधार की दिशा में काम करना, या यदि यह रोजगार सृजन या संपत्ति निर्माण की उच्च क्षमता का एक बड़ा कारोबारी मॉडल है।

स्टार्टअप पंजीकरण आसान बनाने हेतु भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया हब नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन (ऐप) और **www.startupindia.gov.in** नाम से एक वेबसाइट तैयार की है। स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पर एक साधारण फॉर्म भर सकता है और संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकता है। पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

प्रशिक्षण और विकास का तरीका– इस अभियान के सफल प्रक्षेपण के लिए सभी आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएम, एनआईटी और भारत के अन्य संस्थानों के बीच समन्वय और सहयोग किया जाता है। देश के ऊर्जावान और सक्षम युवाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस अभियान के लिए बेहतर लक्ष्य बना सकें।

महिलाओं के लिए स्टार्ट अप इंडिया– स्टार्ट अप इंडिया की पहल का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग से संबंधित महिला समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। महिलाओं के लिए किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने का प्रमुख कारक पूंजी है और विभिन्न बैंक महिला उद्यमियों के लिए विशेष ऋण प्रदान करते हैं जिनके पास संपार्श्विक सुरक्षा, ब्याज दरों आदि से संबंधित नियमों और शर्तों के थोड़े अलग नियम होते है। विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं और ऋणों की एक सूची दी गई है जो उनके लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाता है – जैसे अन्नपूर्णा योजना– स्त्री शक्ति पैकेज–भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन– देना शक्ति योजना– उद्योगिनी योजना– सेंट कल्याणी योजना– महिला उद्योग निधि योजना– महिलाओं के लिए मुद्रा योजना –ओरिएंट महिला विकास योजना आदि। संक्षेप में कहें तो नवाचार का जुनून ही स्टार्टअप की सफलता का मूल मंत्र है।

ऋतु लाम्बा
उप कंपनी सचिव, कार्पोरेट कार्यालय

हिंदी की कुछ उपयोगी वेबसाइटें

क्र.सं.	वेबसाइट का नाम		यूआरएल
1	**हिंदी साहित्य चौनल–** आपको हिंदी विषय से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगी। जिसमें हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक सम्मिलित होंगे।		**https://www.hindisahity.com**
2	**साहित्य मंजरी–** देश विदेश के कोने–कोने से भेजी गयी समकालीन रचनाकारों की नवीन कविता, कहानी, गजल, लेख , समीक्षा इत्यादि।		**https://sahityamanjari.com**
3	**हिंदीकुंज डॉट कॉम–** हिंदी व्याकरण, हिंदी पत्र लेखन, हिंदी निबंध आदि का संकलन है।		**https://www.hindikunj.com/**
4	**रफ्तार–** खबर, शब्दकोश, ज्योतिष, स्वास्थ्य आदि विषयों से संबंधित लेखों का संकलन है।		**https://www.raftaar.in/**
5	**वेबदुनिया–** वेबदुनिया एक भारतीय समाचार जालस्थल है। यह हिंदी के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगू आदि भाषाओं में उपलब्ध है।		**https://hindi.webdunia.com/**

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थिति – सरकारी समर्थन, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) पिछले पांच दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवंत और गतिशील क्षेत्र बना हुआ है। भारतीय एम.एस.एम.ई. क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और प्रतिकूलताओं को दूर करने में लचीलापन प्रदान करता है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए, 6 करोड़ से अधिक एम.एस.एम.ई. आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक तरह से ये छोटे आर्थिक इंजन होते हैं जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत तक का योगदान देते हैं। एम.एस.एम.ई. देश के लगभग आधे निर्यात में योगदान देते हैं। इतना ही नहीं, एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में लगभग 11 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका चलती है।

एम.एस.एम.ई. न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजीगत लागत पर बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी मदद करते हैं। ये उद्यम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में मदद करते हैं और राष्ट्रीय आय और धन का समान वितरण सुकर बनाते हैं। एम.एस.एम.ई. सहायक यूनिटों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और देश के सामाजिक–आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। बड़े उद्योगों को सहायता प्रदान करने के अलावा, एम.एस.एम.ई. ने रोजगार सृजन के संदर्भ में राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें से 55% से अधिक उद्यम देश के छ: प्रमुख राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में स्थित हैं ।

नई परिभाषा

कोविड–19 महामारी के बाद और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत मई 2020 में एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में संशोधन की घोषणा की गई। 2006 में एम.एस.एम.ई. विकास अधिनियम के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संभव हुआ। व्यापार करना आसान बनाने की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक नौकरियां पैदा होंगी। नई परिभाषा से एम.एस.एम.ई. के सुदृढ़ीकरण और वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। विशेष रूप से, कुल कारोबार के आंकड़े से निर्यात को बाहर करने के प्रावधान से एम.एस.एम.ई. अधिकाधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंग।

एम.एस.एम.ई. को सहायता पैकेज देने के लिए केबिनेट की मंजूरी –

1. एम.एस.एम.ई. को इक्विटी समर्थन प्रदान करने के लिए सहायक ऋण के रूप में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 2 लाख संकटग्रस्त एम.एस.एम.ई. को संबल मिलेगा।

2. निधियों की निधि यानी 'फंड ऑफ फंड्स' द्वारा एम.एस.एम.ई. के लिए 50000 रुपये करोड़ की इक्विटी सहायता दी जाएगी। इससे एम.एस.एम.ई. की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस मदद से लघु उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्राप्त होगा।

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए इस पैकेज के तहत विभिन्न घोषणाएँ की गई हैं जिनमें उल्लेखनीय हैं –

➢ परिचालन संबंधी देयताओं को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और कारोबार फिर से शुरू करने के लिए एम.एस.एम.ई. को तीन लाख करोड़ का गैर–जमानती स्वचालित ऋण,

➢ लघु उद्यमों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में संशोधन,

➢ देशी उद्यमों को अधिक अवसर देने के लिए रु. 200 करोड़ तक की खरीद में विदेशी निविदाओं को अनुमत न करना,

➢ सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों द्वारा 45 दिनों के भीतर एम.एस.एम.ई. को बकाया राशि का भुगतान अनिवार्य बनाना।

एम.एस.एम.ई. का अर्थव्यवस्था में योगदान

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि यह लगभग 30 मिलियन यूनिटों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है, लगभग 70 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45% का और निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। इसके अलावा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र 2022 के अंत तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करने की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद करेगा।

हालांकि एम.एस.एम.ई. के कारण कुल उद्यमों, रोजगार और बाजार में अचल परिसंपत्तियों का मूल्य क्रमशः 4.38%, 4. 75% और 6.64% तक बढ़ा है, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का योगदान या एमएसएमई के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान क्रमशः 1.53% और 1.82% है। भारत को अपनी जनसंख्या के अनुरूप रोजगार प्रदान करने के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 10से 15 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

'वन नेशन वन कार्ड' योजना और 'आजीविका' ऐप जैसी अन्य पहलें अभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनसे नियोक्ताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध श्रम का उपयोग करने और उत्पादन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी जो कोविड–19 के कारण बंद पड़े थे।

एम.एस.एम.ई. की चुनौतियाँ – एम.एस.एम.ई. पिछले वर्षों बेहद कठिन दौर से गुजरे हैं । लघु उद्यमों को लगातार अनेक संकटों का सामना करना पड़ा है। कुछेक प्रमुख अवरोध और चिंताएँ इस प्रकार हैं –

बैंकों से पर्याप्त ऋण न मिलना – एम.एस.एम.ई. को बैंकों से ऋण की अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। बैंकों की ऋण प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसलिए उच्च लागत प्रसंस्करण शुल्क के साथ बहुत सारे प्रलेखन की आवश्यकता होती है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा – एम.एस.एम.ई. को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध करा रही हैं।

कमजोर बुनियादी ढांचा– एम.एस.एम.ई. तेजी से विकसित हो रहे हैं लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। खराब बुनियादी ढांचे के कारण उत्पादन लागत अधिक और उत्पादन क्षमता कम होती है।

संसाधनों की अनुपलब्धता – कच्चे माल, कार्य बल और बाजार संबंधी अन्य सूचनाओं के अभाव में ऐसे उद्यम कम कीमत पर उत्पादों का उत्पादन करने में असमर्थ होते हैं।

उन्नत प्रौद्योगिकी का अभाव– एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में, उत्पादन की उन्नत तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है । वे माल के उत्पादन के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

एम.एस.एम.ई. या तो कई दशक पहले स्थापित औद्योगिक सम्पदा में स्थित हैं या शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क आदि सहित बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब है, जिससे लेनदेन की लागत अधिक होती है।

रियल एस्टेट और ऑटो क्षेत्र में आई आर्थिक मंदी, जबकि अधिकांश एम.एस.एम.ई. पूर्तिकर्ताओं के मुख्य स्रोत थे।

देनदारियाँ – एम.एस.एम.ई. पहले ही अदत्त वेतन के भारी वित्तीय बोझ का सामना कर रहे थे जिसके कारण अंततः इस क्षेत्र में अनेक लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। घाटे का तुलन–पत्र उन्हें आरबीआई के मानदंडों के अनुसार बैंकों या एनबीएफसी से कोई वित्त प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता है। अब कोविड–19 महामारी ने एम.एस.एम.ई. को हिलाकर रख दिया है।

सरकार का उल्लेखनीय समर्थन – भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. को देश के भीतर और बाहर दोनों जगह अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने के अनेक पहल किए हैं। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठन देश भर में प्रदर्शनियों / मेलों और क्रेता–विक्रेताओं की बैठक आयोजित करते हैं, जिससे एम.एस.एम.ई. को अपने उत्पादों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) ने एक बी–2–बी वेब पोर्टल लॉन्च किया है और एम.एस.एम.ई. को घरेलू और वैश्विक बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल की स्थापना की है। मंत्रालय ने एम.एस.एम.ई. के लिए एक सार्वजनिक खरीद नीति भी तैयार की है, जो उन्हें अपने उत्पादों के विपणन और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ उत्पादन/सेवा मूल्य श्रृंखलाओं में दीर्घकालिक संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी। माल और सेवाओं की सरकारी खरीद में एम.एस.एम.ई. की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ई–मार्केटप्लेस (जेम) पहले ही स्थापित कर चुकी है। जेम की स्थापना के बाद से एम.एस.एम.ई. को 20000 करोड़ रुपये तक के आदेश मिले हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ–साथ, भारत और चीन के बीच मौजूदा तनाव ने स्थानीय रूप से निर्मित सामानों की मांग बढ़ाई है जिसके चलते भारतीय एम.एस.एम.ई. को नए अवसर मिले हैं।

एम.एस.एम.ई. के पास अब एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम (ईएम)–II या उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) आदि जैसे पंजीकरण हैं। एम.एस.एम.ई. के लिए नया पंजीकरण पोर्टल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा SPICe + नामक एक नया वेब फार्म शुरु करने के चार महीने बाद शुरु किया गया है। इस नए फॉर्म में नाम आरक्षण, निगमन, डीआईएन आवंटन, पैन/टैन/ईपीएफओ पंजीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना, पेशे का पंजीकरण अनिवार्य करना, कंपनी के लिए बैंक खाता खोलना अनिवार्य बनाना और लागू होने पर जीएसटिन का आवंटन आदि जैसी 10 सेवाएं शुरु की गई हैं। ये सेवाएं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग और महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच संबंधों और समन्वय को बेहतर बनाने के भी प्रयास कर रही है। संक्षेप में कहें तो सरकार ने अपनी विभिन्न नवोन्मेषी योजनाओं से एम.एस.एम.ई. के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है।

एम.एस.एम.ई. में महिलाओं की भागीदारी– एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी अनेक पहल की है। इन पहलों के कारण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (पी.एम.ई.जी.पी.) के तहत 1.38 लाख परियोजनाएँ महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई हैं। इस प्रोग्राम के तहत स्थापित कुल परियोजनाओं में लगभग 30% परियोजनाएँ महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई हैं।

मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन केंद्र, सिलाई यूनिट आदि शुरु करने के लिए रु. 50000/– से लेकर 50 लाख तक के ऋण दिए जाते हैं। पी.एम.ई.जी.पी. द्वारा शुरु की गई ट्रेड योजना के तहत महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण और परामर्श दिया जाता है। महिला उद्यम निधि योजना के तहत महिलाओं को रु. 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे 10 वर्षों तक चुकाया जा सकता है। खानपान में रुचि रखने वाली महिलाओं के लिए

अन्नपूर्णा योजना शुरु की गई है जिसमें वे रु. 50000/– तक का ऋण प्राप्त कर सकती हैं। स्त्री शक्ति योजना के तहत रु. 2 लाख तक का ऋण मात्र 0.05 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है। इसी तरह उद्योगिनी योजना कृषि, खुदरा और इसी तरह के अन्य छोटे कारोबार शुरु करने वाली 18 से 45 वर्षीय महिलाओं के लिए है जिसमें उन्हें रु. 1 लाख तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है। इन योजनाओं में अ.जा. / अ.ज.जा. वर्ग की महिलाओं को लिए अतिरिक्त रियायत का प्रावधान भी है।

कोविड–19 के बाद एम.एस.एम.ई. का पुनर्जीवन

- गैर–जमानती स्वचालित ऋण से छोटे कारोबारियों को महामारी का प्रभाव कम करने का मौका मिलेगा।
- आर्थिक प्रोत्साहन से कई एस.एम.ई. को अपना कामकाज दोबारा शुरु करने में मदद मिलेगी और वे महामारी के दौरान हुई आर्थिक हानि से उबर सकेंगे।
- अधिकांश परिवहन उद्योग विनिर्माण क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं, सरकार द्वारा घोषित इन राहत उपायों से छोटे और मझोले उद्यम अपने माल की आवाजाही कर सकेंगे और परिवहन उद्योग में भी जान आएगी।
- व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के प्रतिस्थापन के रूप में सभी एम.एस.एम.ई. के लिए ई–मार्केट लिंकेज प्रदान किया जाएगा। यह आर्थिक प्रोत्साहन भारतीय व्यवसायों के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा।
- आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज स्थानीय दुकानों पर केंद्रित है – जो 40% रोजगार पैदा करते हैं और खुदरा कारोबार का 90% से अधिक हिस्सा चलाते हैं। सरकार के इन सार्थक प्रयासों से हम अर्थव्यवस्था को उसकी पटरी पर वापस ला सकेंगे और इस तरह, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सकेंगे।
- वैश्विक निविदाओं को 200 करोड़ रुपये तक की खरीद से प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले से ई–खरीद साइटों पर एम.एस.एम.ई. के पंजीकरण में वृद्धि हुई है।

एम.एस.एम.ई. को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय

प्रतिभा आकर्षण– एम.एस.एम.ई. को खुद को अलग करने, आला ब्रांड बनाने और प्रतिभा को आकर्षित करने की आवश्यकता है। एम.एस.एम.ई. विकासशील संगठन हैं और संगठन के साथ बढ़ने के लिए नए युवा और उद्यमी कारोबारियों को सहयोग का हाथ बढ़ाने की आवश्यकता है। एम.एस.एम.ई. के कर्मचारियों को इस तथ्य से अवगत कराना अनिवार्य है कि एक छोटी सी फर्म में जोखिम और जिम्मेदारी का स्तर एक बड़ी फर्म की तुलना में अधिक होता है। यह महत्वपूर्ण है कि एम.एस.एम.ई. की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और किसी व्यक्ति को काम पर रखने के लिए मुख्य मापदंड और उसकी भूमिका की सफलता के कारकों के बारे में स्पष्ट रूप से संवाद किया जाए। इस संवर्ग के संगठनों को अधिक लचीले और नए लुभाने वाले लाभों / पुरस्कारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

प्रतिभा धारण– प्रतिभा बनाए रखने के लिए एम.एस.एम.ई. को कार्य–निष्पादन आधारित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन की संस्कृति मेधावी हो जहां कर्मचारियों को उनके कार्य–निष्पादन के आधार पर अधिक जिम्मेदारी दी जाती है। यह तय करने के लिए सुदृढ़ कार्य–निष्पादन प्रबंध प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिए। एम.एस.एम.ई. का नेतृत्व करने वालों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों की क्षमता के साथ न्याय कर पाते हैं और संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उस क्षमता का बेहतर दोहन कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग– प्रौद्योगिकी को अपनाना एक अन्य कारक है जो एम.एस.एम.ई. को प्रक्रिया दक्षता में सुधार करने, लागत को कम करने और कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। क्लाउड और क्लाउड–आधारित प्रौद्योगिकियों के आगमन से वे डिजिटलीकरण का समर्थन करने के लिए बड़े उद्यमों की तुलना में आसानी से एक लोचदार आईटी बुनियादी ढांचा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामाजिक दूरी और सुरक्षा नियमों

का पालन करते हुए क्लाउड–आधारित समाधान कारोबार को चालू रखने में मदद कर सकते हैं।

साझेदारी– एम.एस.एम.ई. के लिए साझेदारी करना आय अर्जित करने का एक और उपाय हो सकता है। विशेष रूप से नवोदित क्षेत्रों में, एम.एस.एम.ई. भारतीय बाजार का पता लगाने या कम लागत वाले विनिर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। ऐसी साझेदारी एम.एस.एम.ई. के लिए कम जोखिम और किफायती माध्यम भी हो सकती है।

मानव संसाधन प्रबंधन – भविष्य में बढ़ती अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप एम.एस.एम.ई. और एसएमई की वृद्धि देखी जाएगी। यदि इन छोटे व्यवसायों को बड़े दिग्गजों के साथ जीवित रहना है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि संगठन में लंबे समय तक योगदान देने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि, लक्ष्य और कैरियर की संभावना हो। एम.एस.एम.ई. को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मानव संसाधन की भूमिका को इस तरह से संरेखित करें कि यह सीधे उनके व्यवसाय के क्षेत्र में संगठन के निचले स्तर पर योगदान दे। संगठन में प्रतिभा आकर्षण, प्रतिभा धारण, योग्यता और कौशल विकास की समस्याएँ उत्पन्न न हो, इसलिए उन्हें प्रभावी मानव संसाधन योजना बनाने और प्रभावी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता होगी।

भविष्य – बहुधा एम.एस.एम.ई. का उल्लेख रोजगार, आर्थिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास में उनके योगदान के संदर्भ में किया जाता है जो सही भी है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि ये उद्यम निर्वहनीय हों और प्रमात्रा और गुणता दोनों में आगे बढ़े। निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, भारतीय एम.एस.एम.ई. को अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी ताकत नहीं माना जाता है । भविष्य की बात करें तो एम.एस.एम.ई. की अगली पीढ़ी तैयार करने में चुनौतियां तो हैं लेकिन सच यह भी है कि ऐसे उद्यम ही अर्थव्यवस्था को सबल बनाते हैं। वैश्विक स्तर पर गहन प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण से पैदा होने वाली मांगों के साथ, अब भारतीय एम.एस.एम.ई. के लिए यह अनिवार्य बन गया है कि वे अधिक प्रतिस्पर्धी बनें, खुद को रणनीतिक रूप से तैयार करें और वैश्विक स्तर पर अपनी मौजदगी दर्ज कराएं।

भारत का गतिशील और जीवंत आर्थिक आधार इन अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगले 20 वर्षों में 8.5 से 9 प्रतिशत की लक्षित वार्षिक जीडीपी विकास दर हासिल करने से प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में चौगुनी वृद्धि होगी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत बहुत कम होगा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत को 2020 के अंत तक जीडीपी के संदर्भ में 207 देशों में चौथे स्थान पर ले आएगा।

संदर्भ स्रोत– फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, **cleartax.in, msme.gov.in**

श्रीनिवास राव,
अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय

कुछ रोचक तथ्य

- खाने का स्वाद उसमें सलाइवा (लार) मिलने के बाद ही आता है।
- शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से बड़ी होती हैं।
- दुनिया के 85 प्रतिशत पौधे समुद्र के अंदर होते हैं।
- एक केकड़े का खून रंगहीन होता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद यह नीला हो जाता है।
- अंग्रेजी अल्फाबेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला लेटर E है।
- इंसान की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है।
- बिल्लियां अपनी जिंदगी का 66 प्रतिशत हिस्सा सोते हुए गुजारती हैं।

रक्षामंत्री ने बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित उत्पादों को लॉन्च किया

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी, उद्घाटन समारोह के दौरान अपना वक्तव्य देते हुए

माननीय रक्षामंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी ने 13 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित दो उत्पादों– लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर (एलवीडीटी) और 1kW ट्रांसमीटर एरियल स्विचिंग रैक को लॉन्च किया।

इस अवसर पर श्री गौतम एम वी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीईएल ने माननीय रक्षामंत्री को इन उत्पादों पर एक प्रस्तुति दी, जिन्हें बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। आत्मनिर्भरता की दिशा में इस उत्पाद का विकास भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और अगले दो से तीन वर्षों के समय में इससे लगभग रु. 100 करोड़ तक विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत बीईएल ने एटीडीएस मारीच विनिर्माणी सुविधा अपग्रेड किया

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी ने 10 अगस्त, 2020, को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्नत, अत्याधुनिक मारीच एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। श्री गौतम एम वी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बीईएल ने इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री को उन्नत टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम (एटीडीएस) मारीच पर एक प्रस्तुति दी। बीईएल की यह पहल माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप है। स्वदेशी रूप से विकसित मारीच प्रणाली आत्मनिर्भर भारत' की ओर एक बड़ा कदम है क्योंकि इसकी प्रत्येक प्रणाली से देश को लगभग यूएसडी 4 मिलियन की बचत होती है।

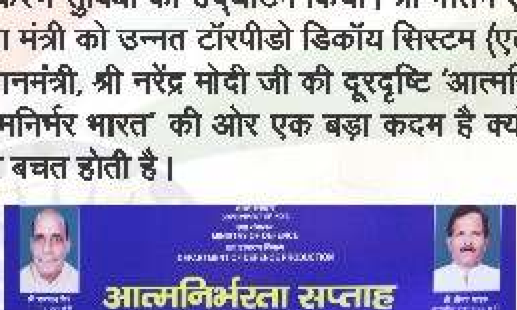

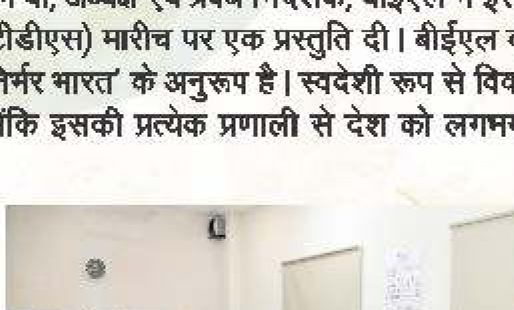

न्यूकट्रल बॉयेंसी परीक्षण सुविधा

इलेक्ट्रॉनिक केबिनेट के लिए बे

रैंप स्ट्रक्चर सुविधा

टाउड ऐरे असेंबली

बीईएल ने 30,000 वेन्टिलेटर बनाने की उपलब्धि हासिल की

ारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), रक्षा मंत्रालय के अधीन नवरत्न पीएसयू ने कोविड –19 महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में भारत सरकार की मदद करने हेतु रिकार्ड समय में 30,000 आईसीयू वेन्टिलेटरों का निर्माण किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की स्वास्थ्य–सेवा अवसरंचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए अप्रैल 2020 में इन 30,000 आईसीयू वेन्टिलेटरों का आदेश दिया था।

बीईएल इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देती है। बीईएल को डीआरडीओ, स्कैनरे तथा उद्योग के अन्य सभी साझेदारों को चिकित्सा श्रेणी के उपकरणों को स्वदेशी रूप से बनाने और देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए एक सक्षम परितंत्र तैयार करने में भारत सरकार की पहल का हिस्सा बनने पर गर्व है। यह भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक सच्चा उदाहरण है।

रणनीतिक उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए बीईएल का ई.ओ.आई. जारी

माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत पाँच उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए अंतर सरकारी करार और मेक–II वर्ग के तहत नवरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा जारी किए जा रहे रुचि प्रकटण (ई.ओ.आई.) प्रस्ताव के अनुरोध (आर.एफ.पी.) की घोषणा वीडियो कॉनफ्रेंसिग द्वारा की। इस अवसर पर श्री गौतम एम वी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, बीईएल ने पाँच उत्पादों ब्रेजिंग वायर, मोशन प्लेटफार्म, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम और पेलोड 1000–2000कि.ग्रा., छोटे आर्म सिम्यूलेटरों के लिए डमी वेपन, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर और 62 X डे जूम लैन्स पर माननीय रक्षा मंत्री जी को प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रेमचंद पुरस्कार योजना

कार्यपालक वर्ग

ऋतु लाम्बा
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

जे. बलराम सिंह
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

जितेंद्रिय नायक
द्वितीय, कार्पो. बैंगलूर

नीरज कुमार चड्ढा
द्वितीय, कार्पो. बैंगलूर

शिवकुमार के
तृतीय, कार्पो. बैंगलूर

चंद्रकला बाई एच
तृतीय, कार्पो. बैंगलूर

गैर–कार्यपालक वर्ग

कविता के.पी.
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

उषा एल
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

प्रियतोष दत्ता
द्वितीय, क्षे.का. कोलकाता

दीपू बी
द्वितीय, कार्पो. बैंगलूर

देविका बी.पी.
तृतीय, कार्पो. बैंगलूर

अनिता रॉड्रिक्स
तृतीय, क्षे.का.मुंबई

जयशंकर प्रसाद पुरस्कार योजना

कार्यपालक वर्ग

शब्बीर अहमद
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

सामिनादने
प्रथम, कार्पो. बैंगलूर

मानस रंजन मिश्रा
प्रथम, क्षे.का. कोल.

नितिन के पाटील
प्रथम, क्षे.का. मुंबई

तमल सेनगुप्ता
प्रथम, क्षे.का. कोल.

पी विनय कुमार
द्वितीय, क्षे.का. चैन्नै

बिप्लव कुमार कर
द्वितीय, क्षे.का. कोल.

पुष्पवल्ली टी
द्वितीय, कार्पो. बैंगलूर

सी.एच. दत्तु
द्वितीय, क्षे.का. चैन्नै

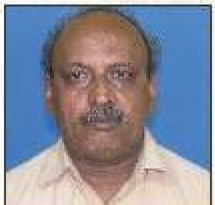
श्रीनिवास एस.एस.आर.
द्वितीय, कार्पो. बैंगलूर

पिंटू दे
तृतीय, क्षे.का. कोल.

एस रवि तेजा
तृतीय, क्षे.का. चैन्नै

सुब्रत सरकार
तृतीय, क्षे.का. कोल.

ई.ए. हरिहरन
तृतीय, कार्पो. बैंगलूर

अजय अग्रवाल
तृतीय, क्षे.का. कोल.

नव प्रभा

प्रदीप कुमार पांडे
चतुर्थ, क्षे.का.दिल्ली

अमरजीत सिंह बी.के.
चतुर्थ, कार्पो बेंगलूर

बेबी शांता
प्रोत्साहन, कार्पो बेंगलूर

आयुषी गर्ग
प्रोत्साहन, कार्पो बेंगलूर

विवेक साहू
प्रोत्साहन, क्षे.का. [illegible]

शशि कुमार पृथ्वी
प्रोत्साहन, क्षे.का. [illegible]

गैर–कार्यपालक वर्ग

वाणिश्री पी
प्रथम, कार्पो बेंगलूर

सुनीता आर
प्रथम, कार्पो बेंगलूर

आरती सी बुदपनवार
प्रथम, कार्पो बेंगलूर

शारदा सी.एच.
प्रथम, कार्पो बेंगलूर

शकुन्तला एन सी
प्रथम, कार्पो बेंगलूर

किरण देठे
द्वितीय, क्षे.का. मुंबई

सुधा जानकी पी.एस.
द्वितीय, कार्पो बेंगलूर

राजेश्वरी बी
द्वितीय, कार्पो बेंगलूर

प्रीता एम
द्वितीय, कार्पो बेंगलूर

शर्मिला एन
द्वितीय, कार्पो बेंगलूर

शांतनु भट्टाचार्या
द्वितीय, क्षे.का.कोलकाता

मानसा सवका पी आर
तृतीय, कार्पो बेंगलूर

शिव शंकर एस.आर.
तृतीय, कार्पो बेंगलूर

शकुंतला बाई
तृतीय, कार्पो बेंगलूर

धीरज परमार
तृतीय, क्षे.का. मुंबई

शिवनाथ कणसे
तृतीय, क्षे.का. मुंबई

राकेश कुमार
तृतीय, कार्पो बेंगलूर

अनुसूया रावत
चतुर्थ, क्षे.का. दिल्ली

प्रसन्न कुमार जाधव
चतुर्थ, क्षे.का. मुंबई

संजय मारुति बोंबे
चतुर्थ, क्षे.का. मुंबई

टी.वी. राव
चतुर्थ, क्षे.का.[illegible]

सुमित्रा देवरानी
चतुर्थ, क्षे.का. दिल्ली

प्रदीप बिजलवान
चतुर्थ, क्षे.का. दिल्ली

पवन कुमार
चतुर्थ, क्षे.का. दिल्ली

कबीर पुरस्कार योजना

श्री मनोज यादव
कार्पो बेंगलूर

नागार्जुन पुरस्कार योजना

देवराज
प्रथम, गा.बाद

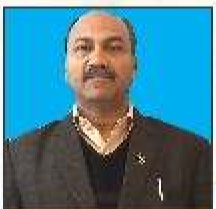
अमरीक सिंह
द्वितीय, गा.बाद

सागर अग्रवाल
तृतीय, गा.बाद

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

बी ई एल गीत

देश की रक्षा अपना फर्ज़ है,
भारत की है शान बी ई एल ।
भूमि जल हो या हो आसमान,
वीर जवानों के साथ खड़े हरदम,
अंधेरे में भी हम राह को रोशन करें
बी ई एल । बी ई एल । बी ई एल ।
दशा दिशा का पता बताएं शान से खड़ी रेडारें,
कंधों पर सजते हैं संचार यंत्र हमारे,
जहाज़ हो या अंतरिक्ष यान उनमें तंत्र हमारे,
शिक्षण हो या प्रसारण साथ हैं यंत्र हमारे,
जन जन का सहयोग करें हम,
मतदान को आसान करें हम,
नावु बी ई एल । मेमू बी ई एल ।
आपण बी ई एल । नांगल बी ई एल ।
आमरा बी ई एल । हम है बी ई एल ।
बी ई एल । बी ई एल । बी ई एल ।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
गुणता, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष

बीईएल द्वारा निर्मित सी वी 200 वेन्टीलेटर

रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, उससे बढ़कर

नवरत्न पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कोविड–19 महामारी से लड़ने के अपने प्रयासों में भारत सरकार की मदद करने हेतु रिकार्ड समय में 30,000 आईसीयू वेन्टिलेटरों का सफल निर्माण किया।

भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का एक सच्चा उदाहरण

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम
पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलुरु - 560 045 भारत

टोल फ्री नंबर - 1800 4250433
सीआईएन नं.- L32309KA1954GOI000787
www.bel-india.in

राष्ट्र के रक्षा बलों को सशक्त बनाते हुए